नई दिल्ली ■ गुरुवार 05 फरवरी 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 309 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 मणिपुर में खेमचंद सिंह की... | 07 एशियाई चैंपियनशिप: पिस्टल शूटर ईशा सिंह ने भारत को दिलाए दो स्वर्ण पदक | 'मां बहन' में कॉमिक अंदाज में नजर आयेंगी तृप्ति डिमरी 08

विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक दिनभर के लिए स्थगित

नई दिल्ली। विपक्ष के भारी हंगामें के कारण बुधवार को लगातार तीसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। बार-बार के व्यवधान और तीन स्थगनों के बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके चलते पहले 12 बजे और फिर 02 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

दोपहर बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई लेकिन वह भी अधिक देर तक नहीं चल सकी। इसके बाद सदन की कार्यवाही शाम 05 बजे तक के लिए स्थगित की गई। शाम को भी हंगामा जारी रहने पर लोकसभा को अगले दिन गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कुछ पुस्तकों का हवाला दिया। निशिकांत ने कहा कि एक

किताब पर चर्चा चल रही है, किताब प्रकाशित नहीं हुई है। वे उन किताबों के बारे में बताना चाहते हैं जिनमें नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के बारे में लिखा गया है। यह किताबें छपी हुई हैं।

इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने लगातार विरोध किया, जिसके कारण कार्यवाही बाधित होती रही। पीठासीन अधिकारी ने उन्हें अध्यक्ष की व्यवस्था का हवाला देते हुए विषय से संबंधित बात रखने को कहा। दूसरी ओर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके चलते सभा की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित कर दी गई। शाम में कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी के बोलने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप तक पहुंच गए, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को लेकर पिछले दो दिनों से विवाद बना हुआ है।

राहुल गांधी पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक से जुड़े संदर्भ रखना चाहते थे, जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने नहीं दी जा रही है। इसी से जुड़े हंगामे के दौरान मंगलवार को विपक्ष के 8 सांसदों को सदन से निलंबित भी किया गया था।

राहुल ने बिट्टू को 'गद्दार' कहा; भाजपा ने सिख समुदाय का अपमान बताया

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को 'गद्दार' कहा कि हालांकि उनकी इस टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सिखों का अपमान करार दिया और कहा कि इससे यह समुदाय आहत है। हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि बिट्टू सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते तथा उन्होंने पार्टी (कांग्रेस) से उस वक्त विश्वासघात किया, जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा था तथा पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

वाई खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली

दो उपमुख्यमंत्रियों ने भी संभाला पदभार

इंफाल। भाजपा नेता वाई खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 62 वर्षीय सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुकी समुदाय से ताल्लुक रखने वालीं भाजपा विधायक नेमचा किपगेन और नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के विधायक एल. डिखो ने मणिपुर के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।

किपगेन ने नयी दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से ऑनलाइन माध्यम से शपथ ली। भाजपा के गोविंदास कोंथौजम और एनपीपी नेता के. लोकेन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के कुछ घंटों बाद यहां 'लोक भवन' में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अशांत मणिपुर पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन था। शपथ ग्रहण समारोह में कई भाजपा विधायक, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य के शीर्ष राजग नेता शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने युमनाम खेमचंद को दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक एक्स पोस्ट में मोदी ने कहा कि युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं नेमचा किपगेन और लोसी दिखो को राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर और कोंथौजम गोविंददास सिंह के साथ-साथ खुराईजम लोकेन सिंह को मणिपुर सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि वे मणिपुर के मेरे भाइयों और बहनों के लिए विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में लगन से काम करेंगे।

सिंह को मंगलवार को नयी दिल्ली में भाजपा विधायक दल का नेता और उसके बाद राजग विधायक दल का नेता चुना गया।

पिछले साल नौ फरवरी को मेइती और कुकी समुदायों के बीच महीनों तक जारी रही जातीय हिंसा के बाद बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस्तीफे दे दिया था, जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

संक्षिप्त खबरें

जनगणना 2027: दूसरे चरण में होगी जाति की गणना, डिजिटल माध्यम से होगा पूरा अभ्यास

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना 2027 के दौरान जाति गणना की जाएगी। यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में पूछे गए दो अलग-अलग प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी। मंत्री ने बताया कि भारत में जनगणना का संचालन दो चरणों में किया जाता है। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस (एचएलओ) के तहत मकान की स्थिति, संपत्ति, सुविधाओं आदि से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। इस चरण के लिए प्रश्नों को 22 जनवरी को अधिसूचित किया जा चुका है। दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जाति संबंधी विवरण जुटाए जाएंगे।

आरोन जॉर्ज का शतक, भारत अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में

हरारे। भारत ने आरोन जॉर्ज (115 रन) के शानदार शतक के साथ आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी (68 रन) और आयुष म्हात्रे (62 रन) की धमाकेदार अर्धशतकीय पारियों की मदद से बुधवार को यहां अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। भारत अब शुक्रवार को यहां फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा। यह अंडर-19 टूर्नामेंट में भारत का 10वां फाइनल होगा। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए फैसल शिनोजादा (110) और उजैरुल्लाह नियाजई (101) के शतकों की मदद से 310 रन बनाए। लेकिन भारत ने यह लक्ष्य 41.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस तरह अंडर-19 विश्व कप में भारत ने अब तक के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा किया। आरोन (104 गेंद, 15 चौके, दो छक्के) ने बेहतरीन शॉट्स की मदद से शतक जड़ा।

उप्र के संविदा शिक्षक 17 हजार वेतन पाने के हकदार: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के हजारों संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को फैसला सुनाया कि वे 2017-18 से 17 हजार रुपये मासिक वेतन पाने के हकदार हैं और उनके अनुबंध की समाप्ति के बाद उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त माना जाए। न्यायालय ने कहा कि इन शिक्षकों का पारिश्रमिक हमेशा के लिए 7,000 रुपये तय करने जैसा अन्यायपूर्ण तरीका जबरन काम कराने और 'बेगार' के समान है, जिसपर संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत कड़ी पाबंदी है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक अपील खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति पंकज मिश्रा और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने राज्य को आदेश दिया कि वह एक अप्रैल 2026 से इन शिक्षकों को प्रति माह 17,000 रुपये के हिसाब से मानदेय देना शुरू करे, और बकाया राशि का भुगतान आज से छह महीने के अंदर किया जाए।

आपात स्थिति में कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरा तुर्की एयरलाइंस का विमान

कोलकाता। तुर्की एयरलाइंस के एक विमान के इंजन में खराबी आने के बाद विमान ने कोलकाता हवाई अड्डे पर आपात परिस्थितियों में उतरा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पायलट ने विमान के दाहिने इंजन में आग लगने की सूचना दी थी। यह उड़ान काठमांडू से तुर्किये के इस्तांबुल जा रही थी। बयान के मुताबिक उड़ान संख्या टीएचवाई-727 वाला एयरबस ए330-300 विमान अपराह्न करीब 1.15 बजे काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से चालक दल के 11 सदस्यों सहित 236 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ।एक अधिकारी ने बताया कि पायलट ने उड़ान भरने के दौरान विमान के दो इंजनों में से एक में खराबी की सूचना दी थी।

सीएम ममता को SIR मामले में पैरवी करते देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े वकील और वादी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के अदालत कक्ष में बुधवार को उस समय वकील और वादी उमड़ पड़े जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष अपनी दलीलें रख रही थीं। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में दायर एक मामले में बुधवार को ऐसा किया। पारंपरिक सफेद साड़ी और काले दुपट्टे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी समेत अपने अन्य वकीलों के साथ उच्चतम न्यायालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचीं।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत के परिसर में प्रवेश करने के लिए उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री से प्रवेश पास के लिए आवेदन किया था और उन्हें यह पास मिल गया था। बनर्जी के अदालत परिसर में प्रवेश करते ही, वहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने खुशी-खुशी उनकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं और अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे।

एलीवेटर पर कदम रखते समय, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने मीडियाकर्मियों के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या वह स्वयं दलीलें पेश करेंगी। पूर्वाह्न लगभग 10 बजकर पांच मिनट पर बनर्जी अपने वकीलों के साथ प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल हुईं और दर्शकों के लिए लगी एक कुर्सी पर बैठ गईं। दोपहर 12 बजकर 55 मिनट पर जब प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू की, तो उन्हें वकीलों के लिए आरक्षित पहली पंक्ति में देखा गया।

खौफनाक अंत: गेम की लत में नौंवी मंजिल से कूदी तीन सगी बहनें, मौत

गाजियाबाद। गाजियाबाद में मंगलवार देर रात नौवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट की बालकनी से कथित तौर पर कूदने के बाद तीन नाबालिग बहनों की मौत हो गई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस एक ऑनलाइन कोरियन गेम की लत संबंधी पहलू की भी जांच कर रही है।

सहायक पुलिस आयुक्त (शालीमार गार्डन) अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये बहनें एक ऑनलाइन कोरियन गेम 'लव गेम' की आदी थीं जो 'टास्क बेस्ड' है और बच्चियों के माता-पिता उनके बहुत ज्यादा गेम खेलने पर आपत्ति जताते थे। कोरियन 'टास्क-बेस्ड' गेम वह होते है जिसमें खिलाड़ी को लक्ष्य दिए जाते हैं और उसी से गेम आगे बढ़ता है।

पुलिस उपायुक्त निमिष पाटिल ने बताया कि जांच में पता चला कि लड़कियां कोरियन सामग्री से बहुत

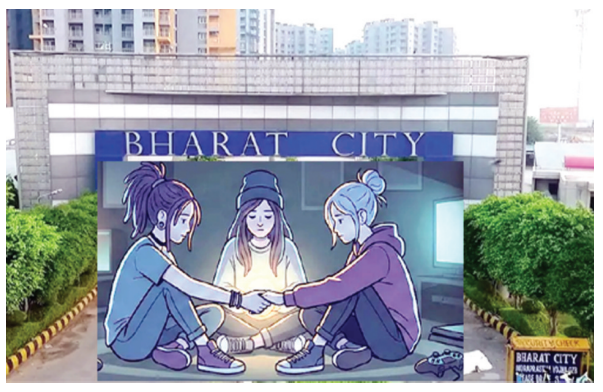

अधिक प्रभावित थीं और अपने मोबाइल फोन पर काफी समय बिताती थीं। उन्होंने कहा, 'परिवारवालों ने पिछले कुछ दिनों से उनके मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, जिससे वे परेशान थीं और संभवतः इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया।' सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस को मंगलवार देर रात दो बजकर 15 मिनट पर सूचना मिली कि साहिबाबाद इलाके में टीला मोड़ थना क्षेत्र में 'भारत सिटी' के एक टावर में नौवीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से तीन लड़कियों ने छलांग लगा दी है।

उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि स्थानीय निवासी चेतन कुमार की तीनों बेटियां निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12), भूतल पर गिरी थीं और बुरी तरह से घायल थीं। उन्हें एम्बुलेंस से लोनी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, बहनें कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन गेम की आदी हो गई थीं और अक्सर लगातार कोरियन गेम खेला करती थीं।

सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि तीनों सब कुछ एक साथ करती थीं- नहाने से लेकर खाने तक और सोने से लेकर स्कूल जाने तक।" पुलिस उपायुक्त पाटिल ने बताया कि लड़कियां पिछले दो वर्ष से स्कूल नहीं जा रही थीं। उन्होंने कहा कि पहले भी पढ़ाई में उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि मोबाइल फोन और गेमिंग की लत उन्हें कब से थी और जांच शुरुआती दौर में है, लेकिन यह साफ है कि लड़कियां मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बहुत अधिक आदी थीं।

किश्तवाड़ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फ से ढके ऊंचे इलाकों में बुधवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पिछले 18 दिनों में चतरू क्षेत्र में यह पांचवीं मुठभेड़ है, क्योंकि सेना और पुलिस, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) संगठन से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह की तलाश कर रही है। किश्तवाड़ क्षेत्र में

आतंकवादियों की निरंतर खोज और उनके खात्मे के लिए घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान कई मुठभेड़ें हुई हैं। इसी क्रम में आज शाम लगभग 5.45 बजे किश्तवाड़ के दिच्छर क्षेत्र में 'काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा', व्हाइट नाइट कोर, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा संचालित संयुक्त अभियान (त्राशी-1) में आतंकवादियों से सामना हुआ। सेना के व्हाइट नाइट कोर्प ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि एक आतंकवादी को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। अभियान जारी है।

नई कर व्यवस्था को अबतक 86 प्रतिशत करदाताओं ने अपनायाः सीबीडीटी चेयरमैन

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि लगभग 86 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाता नयी कर प्रणाली में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। आकलन वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत था।

केंद्र वांगचुक की हिरासत पर पुनर्विचार करे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या इस बात की संभावना है कि वह जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनकी हिरासत पर विचार कर सकती है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी वराले की पीठ ने कहा कि वांगचुक की स्वास्थ्य रिपोर्ट ठीक नहीं है और केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम नटराज को इस मामले में निर्देश लेने चाहिए। अदालत ने कहा कि दलीलों, जवाबी दलीलों और कानूनी पहलुओं के अलावा अदालत का एक अधिकारी होने के अलावा इस बात पर भी विचार करें। लगभग पांच महीने पहले 26 सितंबर 2025 को हिरासत संबंधी आदेश जारी किया गया था। पीठ ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करते समय हमने जो रिपोर्ट देखी है, उससे पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुछ आयु संबंधी और कुछ दूसरी समस्याएं हैं। क्या सरकार की ओर से पुनर्विचार किए जाने की कोई संभावना है? नटराज ने कहा कि संबंधित प्राधिकारियों से सुझाव लेंगे। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक पिछले साल लेह में हुई हिंसा के लिए

जिम्मेदार हैं, जिसमें चार लोगों की मौत हुई और 161 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि अंततः उनके भड़काऊ भाषण, उकसावे के कारण यह सब हुआ। व्यक्ति का सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक नहीं होता, व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करना ही पर्याप्त होता है।

नटराज ने कहा कि वांगचुक के हिरासत आदेश को तीन अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी गई और मंजूरी के आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई। अदालत में दलीलें पेश की जानी बृहस्पतिवार को भी जारी रहेंगी। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) जैसे कठोर कानून के तहत वांगचुक की हिरासत के खिलाफ दायर उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की याचिका पर सुनवाई कर रही है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत होने के दो दिन बाद 26 सितंबर को वांगचुक को हिरासत में लिया गया था।

भारत सिर्फ भूगोल नहीं, सेवा और कल्याण उसका स्वभाव है : भागवत

कसरावद (निमाड़)। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, यहां सेवा, कर्म और सर्वजन कल्याण उसका स्वभाव है। कुछ भी यहां उपकार नहीं बल्कि सेवा ही परंपरा है। जीवन में जहां भी सेवा का अवसर मिले, उसे करना चाहिए क्योंकि सेवा से आत्मशुद्धि होती है। सभी परमेश्वर के स्वरूप हैं, अतः उपकार नहीं, सेवा करना हमारा धर्म है। हमारे यहां चैरिटी नहीं, अपितु सेवा है। जीवन में सेवा के जो भी अवसर मिलें, सेवा करना चाहिए। जिसके पास जो भी सामर्थ्य हो, वही उसे समाज को अर्पित करना चाहिए। जिसके पास जो हो, वो देना चाहिए। सेवा से हमारी शुद्धि होती है।

उक्त विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने

कसरावद में व्यक्त किए। ये विचार-प्रेरक कार्यक्रम निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन एवं श्री रामकृष्ण विश्व सद्भावना निकेतन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर डॉ. मोहन भागवत ने 'मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण' विषय पर उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में 'गोष्ट-नर्मदालयाची' ऑडियोबुक का विमोचन भी किया गया।

सरसंघचालक डॉ. भागवत ने कहा कि मनुष्य सुनकर या बोलकर नहीं, देखकर सीखता है। भारत की यात्रा में यह सत्य स्पष्ट हुआ है कि सुख बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर ही निहित है। भारत में मनुष्य के अंदर की खोज की परंपरा रही है और यही आंतरिक यात्रा शाश्वत सुख का मार्ग है। हमारे पूर्वजों ने अनुभव के आधार पर बताया कि माया का आधार अध्यात्म होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को संवेदना प्रदान की है, जो दूसरों के सुख-दुःख को समझती है। किसी की उपेक्षा करके सुख भोगना मनुष्य की संवेदना के विपरीत है। जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए शिक्षा और शुचिता अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य केवल स्वयं का दुःख दूर करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के दुःख को भी दूर करना है, यही भारत का स्वभाव है। यही धर्म भारत ने विश्व को दिया है और हम पाते हैं कि परतंत्रता के काल में भी यह स्वभाव भारत का नहीं बदला।

प्रदेश सरकार का मिशन : यीडा के सेक्टर-28 में आकार ले रहा मेडिकल डिवाइस पार्क

लखनऊ/नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर-28 में 350 एकड़ में विकसित हो रहा मेडिकल डिवाइस पार्क अब कागजी योजना से निकलकर जमीन पर उतर चुका है, जहां निवेश, आवंटन और निर्माण तीनों स्तरों पर ठोस प्रगति दर्ज की गई है।

योजना के अंतर्गत यहां अब तक न सिर्फ 100 से अधिक प्लॉट्स का आवंटन कर दिया गया है, बल्कि एक दर्जन इकाइयों ने अपना निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। जल्द ही यहां प्रोडक्शन भी शुरू होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विकसित हो रहा मेडिकल डिवाइस पार्क, योगी सरकार के उस विजन का प्रतीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश को नीति, इन्फ्रास्ट्रक्चर व भरोसा, तीनों स्तरों पर निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनाया जा रहा है। यह

पार्क आने वाले वर्षों में यूपी को मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का नया पावरहाउस बना सकता है। मेडिकल डिवाइस पार्क के अंतर्गत 188.15 एकड़ भूमि औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें विभिन्न आकार के कुल 203 इंडस्ट्रियल प्लॉट विकसित किए गए हैं। अब तक 101 प्लॉट का आवंटन हो चुका है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि यीडा क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस सेक्टर को लेकर निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है।

यीडा द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 85 निवेशकों ने लीज प्लान जमा किया है, जबकि 62 लीज डीड निष्पादित हो चुकी हैं। 49 यूनिट्स ने साइट का पजेशन भी ले लिया है। 23 इकाइयों के भवन मानचित्र स्वीकृत हो चुके हैं तो 12 इकाइयों में निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। यह प्रगति योगी सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम, समयबद्ध स्वीकृति और नीति-स्थिरता का सीधा प्रमाण मानी जा रही है। यीडा इस मेडिकल डिवाइस पार्क को केवल एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं, बल्कि एक फुल-फ्लेज्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के रूप में विकसित कर रहा है। इसके तहत 9.02 एकड़ में वेयरहाउस प्लॉट, 18.66 एकड़ में ग्रीन एरिया, 46.43 एकड़ में कॉमन फैसिलिटी एरिया, 4.84 एकड़ में कमर्शियल सेक्टर और 79.10 एकड़ में पार्किंग व रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है, जिससे उत्पादन के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण और वर्कफोर्स सुविधाओं का संतुलन सुनिश्चित हो सके। मेडिकल डिवाइस पार्क में औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध शेष भूमि में से 10.32 एकड़ भूमि पर नए आवंटन के लिए 12 जनवरी 2026 को योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना के तहत कुल 22 नए प्लॉट आवंटन के लिए प्रस्तावित हैं, जिनमें 1000 वर्गमीटर के 11 प्लॉट, 2100 वर्गमीटर के 9 प्लॉट तथा 5940 वर्गमीटर के 2 प्लॉट शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2026 तय की गई है।

योगी मॉडल को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उद्योग विशेषज्ञों का भी मानना है कि यीडा की रणनीतिक लोकेशन, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट इकोसिस्टम के साथ योगी सरकार की उद्योगोन्मुख नीतियों का मेल उत्तर प्रदेश को मेडिकल डिवाइस सेक्टर में राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकता है। यह परियोजना आयात पर निर्भरता घटाने के साथ-साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को भी मजबूती देती है।

- यीडा बना मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र, 101 यूनिट्स को भूमि आवंटन
- मेडिकल डिवाइस पार्क में 188.15 एकड़ भूमि औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित
- 22 नए प्लॉट्स आवंटन के लिए प्रस्तावित, 11 फरवरी तक किया जा सकेगा आवेदन

रेकी कर वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नोएडा। सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का बुधवार को पर्दाफाश कर सरगना समेत छह बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चार कार बरामद हुईं। आरोपी रेकी करने के बाद अब तक 200 से अधिक वाहन चोरी कर चुके हैं।

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संभल निवासी समीर उर्फ दाऊद उर्फ कुंजा और सलीम, दिल्ली निवासी आजाद, राजस्थान के जोधपुर निवासी मोहसिन और फैसल के रूप में हुई। समीर इस गिरोह का सरगना है। उसके खिलाफ दिल्ली और नोएडा के थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। उसने अमरोहा में भी कई वारदातें की हैं। सलीम के खिलाफ सात मामले दर्ज हैं। आजाद के खिलाफ 38 मुकदमे दर्ज हैं।। एक अन्य सलीम के खिलाफ चार केस हैं। मोहसिन के खिलाफ तीन केस दर्ज हैं। फैसल के खिलाफ भी तीन मामले दर्ज हैं।

डीसीपी के अनुसार गिरोह के सदस्य पहले इलाके की रेकी करते। इसके लिए वे टैक्सी का इस्तेमाल करते। रात के समय चालक बदल-बदल कर गिरोह के सदस्य घूमते और यह चिन्हित करते कि किन जगहों पर वाहन आसानी से चोरी किया जा सकता है। जहां सुरक्षा कम होती या वाहन लंबे समय से खड़ा होता, वहां पर नजर रखी जाती। रात के अंधेरे में प्रोग्रामर की मदद से गाड़ी का लॉक तोड़ा जाता। इसके बाद चोरी की गई कार में तुरंत जीपीएस हैमर लगा दिया जाता। इससे वाहन का जीपीएस काम करना बंद कर देता। इसके बाद आरोपी वाहन लेकर भाग जाते। जीपीएस के काम न करने से पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी होती। पिछले 12 वर्ष से वारदात कर रहे एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि गिरोह के बदमाश साल 2013 से लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इतने लंबे समय तक सक्रिय रहने के कारण गिरोह के सदस्य पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे।

आरोपियों ने नोएडा और गाजियाबाद के अलावा अमरोहा और राजस्थान में भी वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी पूर्व में डकैती भी डाल चुके हैं। सभी आरोपी पूर्व में जेल जा चुके हैं। राजस्थान और हरियाणा में बेचे वाहन पुलिस के अनुसार सभी आरोपी पांचवीं से लेकर नौवीं कक्षा तक पढ़े-लिखे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी की गई कारों को वे राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों में ऑन-डिमांड बेचते। जो गाड़ियां नहीं बिक पाती थीं, उनके पुर्जे अलग कर दिए जाते। इन पुर्जों को दिल्ली के अलग-अलग ऑटो पार्ट बाजारों में बेचा जाता। इससे मिलने वाली रकम को गिरोह के सभी सदस्य आपस में बांट लेते।

नोएडा ने अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने वाली सेक्टर-39 थाना पुलिस की टीम को 25 हजार का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें। स्टीयरिंग लॉक और अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को बुल्डोजर से ध्वस्त किया

नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित ग्राम भनौता के खसरा संख्या-135 की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुधवार को बुल्डोजर चलाकर करीब 10 हजार वर्ग मीटर एरिया पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए होने का आकलन है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर परियोजना विभाग की वर्क सर्कल दो की टीम ने यह कार्रवाई की है। कालोनाइजर बाउंड्री कर प्लॉटिंग की कोशिश कर रहे थे। ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी। एसीईओ ने अपील भी की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।

महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने बताया कि ग्राम भनौता के खसरा संख्या 135 की जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। वर्क सर्किल दो की टीम ने प्राधिकरण के सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में मौके पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। दोबारा निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

यमुना विकास प्राधिकरण ने मुक्त कराई 25 हेक्टेयर भूमि

नोएडा । यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिसूचित एरिया में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई। इन दिनों यमुना प्राधिकरण भू-माफियाओं के विरूद्ध एक्शन में है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह के सख्त निर्देश पर प्राधिकरण के आला-अफसरों द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अतिक्रमणों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है।

इसी क्रम में आज यीडा द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध धवस्तीकरण की गई। जिसमें हेरिटेज सिटी एवं राया अर्बन सेंटर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की लगभग 25 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। यह भूमि ग्राम पिपरौली खादर, अरूवा खादर एवं पानी गांव खादर की है, जिसकी अनुमानित

बाजार कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपये आंकी गई है। जानकारी के अनुसार आज मथुरा के हेरिटेज सिटी क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध होटल एवं ढाबों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यमुना नदी के किनारे लगभग दो हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरुद्ध भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हेरिटेज सिटी के कोर एरिया में ग्राम अरूवा खादर एवं ग्राम पिपरौली खादर में दो बड़ी अवैध कालोनियां निर्मित की जा रही थी जिनमें धवस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई।

उल्लेखनीय है कि हेरिटेज सिटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां अवैध रूप से होटल, ढाबे एवं अन्य निर्माण किए जा रहे थे। यह कार्रवाई प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में, डिप्टी कलेक्टर शिव अवतार सिंह, अभिषेक शाही एवं कृष्ण गोपाल त्रिपाठी द्वारा गई।

साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया

ग्रेटर नोएडा। सादोपुर गांव मे चल रहे कुमारी मायावती राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में बुधवार को संकल्प संस्था ने साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया और उससे बचाव के तरीके बताए। संकल्प संस्था के संस्थापक डॉ. भूपेंद्र नागर और सह-संस्थापक अमित नागर ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में साइबर अपराध में वृद्धि है, जो चिंताजनक है। जागरूकता होकर इससे बचा जा सकता है। विद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर डॉ. अनिता रानी राठौर ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। वही मिशन शक्ति अभियान-5.0 के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने बुधवार को महिलाओं को साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया। मिशन शक्ति टीम ने महिला सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं के बारे में बताया।

एमिटी विश्वविद्यालय में विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर रैली और विशेषज्ञ सत्र आयोजित

नोएडा। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2026 के अवसर पर एमिटी विश्वविद्यालय के बायोसाइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ एंड एलाइड साइंसेस डोमेन द्वारा "यूनाइटेड बाय यूनिक" थीम पर एक भव्य कैंसर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों छात्रों और शिक्षकों ने भाग लेकर कैंसर से बचाव और समय पर जांच के संदेश दिए।

रैली के साथ-साथ पोस्टर प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिता और विशेषज्ञ व्याख्यान सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स से जुड़े चिकित्सकों ने कैंसर के लक्षण, रोकथाम और आधुनिक उपचार की जानकारी साझा की। एमिटी की कुलपति डॉ. बलविंदर शुक्ला ने कहा कि समय पर जांच और स्वस्थ जीवनशैली से कई प्रकार के कैंसर रोके जा सकते हैं,

वहीं कैंसर सर्वाइवर काजल प्रसाद ने अपने अनुभव साझा कर छात्रों को सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छाशक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जागरूक कर समाज में कैंसर के प्रति फैले डर और भ्रांतियों को दूर करना रहा, जिससे अधिक से अधिक लोग समय रहते जांच और उपचार की ओर प्रेरित हो सकें।

विश्व कैंसर दिवस पर संस्था ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम

नोएडा। स्मार्ट संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 'सेहत सही लाभ कई' श्रृंखला के अंतर्गत सलाम नमस्ते में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेक्टर 62 स्थित संस्थान परिसर में कार्यक्रम के दौरान जिला तम्बाकू प्रकोष्ठ, गौतमबुद्ध नगर की प्रमुख डॉ. श्वेता खुराना ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान कैंसर की रोकथाम, शीघ्र निदान तथा उपलब्ध उपचार विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बुधवार को कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए डॉ. श्वेता खुराना ने कहा कि सही समय पर जांच, तम्बाकू से दूरी और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हमें यह समझना आवश्यक है कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिससे जूझकर भी हम स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर पाते। कैंसर के लगभग 90 प्रतिशत मामले पर्यावरणीय कारणों से होते हैं, जिनमें तंबाकू एक प्रमुख कारक है। उन्होने कहा कि तंबाकू में मौजूद निकोटिन दुनिया के सबसे हानिकारक रसायनों में से एक है, जो मात्र 8 सेकंड में दिमाग तक पहुंच जाता है। इसका असर जल्दी खत्म हो जाता है, इसी कारण व्यक्ति को बार-

बार इसकी आवश्यकता महसूस होती है। सबसे दुखद बात यह है कि हम गुटखा खाते या सिगरेट पीते हुए व्यक्ति को देखकर भी अक्सर उसे रोकते नहीं हैं, जबकि शराब या अन्य नशा के मामले में परिवार हस्तक्षेप करता है। जो बुराई समाज के सामने होते हुए भी नहीं रोकी जाती, वही सबसे अधिक घातक बन जाती है। सलाम नमस्ते की स्टेशन हेड बर्षा छबारिया ने बताया कि हम फरवरी माह को कैंसर जागरूकता माह के रूप में मना रहे हैं। जिसमे सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम, जागरूकता रैली, शपथ, सामाजिक चर्चा तथा विशेष रेडियो प्रसारण आयोजित किए जाएंगे।

इसके साथ ही कैंसर चैंपियनों की प्रेरणादायक कहानियां भी साझा की जाएंगी, जिससे समाज में सकारात्मक सोच और उम्मीद का संदेश दिया जा सके। वही कार्यक्रम के दौरान युवाओं के साथ कैंसर जागरूकता हेतु शपथ भी दिलाई गयी।

दिल्ली के सभी एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लागू : सीएम

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के अंतर्गत दिल्ली क्षेत्र के सभी 143 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम या एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) लगाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया गया।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वायु प्रदूषण से निपटना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत मेट्रो जैसे व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में अब तक 131 मिस्ट स्प्रे सिस्टम और 12 एंटी-स्मॉग गन स्थापित की जा चुकी हैं। जहां तकनीकी कारणों से मिस्ट स्प्रे लगाना संभव नहीं था, वहां एंटी-स्मॉग गन लगाई गई हैं ताकि प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में कोई कमी न रहे। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत 89 ऑन-रोड और 54 ऑफ-रोड एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। यह पहल राजधानी की हवा की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ यात्रियों और आम नागरिकों को अधिक स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ दिल्ली के सौंदर्यीकरण पर भी सरकार बराबर ध्यान दे रही है। इसी दिशा में दिल्ली मेट्रो के विभिन्न कॉरिडोर पर स्थित 50 पिलर्स पर आर्टवर्क का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन कलाकृतियों में प्रकृति, फूलों, पक्षियों और भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों को उकेरा गया है, जो शहर की पहचान और आकर्षण को और निखारेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प राजधानी को केवल प्रदूषण से राहत दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे एक सुंदर, जीवंत और विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करना है। मेट्रो स्टेशनों पर मिस्ट स्प्रे, एंटी-स्मॉग गन और पिलर्स पर किया गया आर्टवर्क इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। आने वाले समय में भी सरकार पर्यावरण संरक्षण और शहरी सौंदर्यीकरण के लिए ऐसे ही प्रभावी कदम उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस पूरे अभियान में सहयोग देने वाले सभी विभागों और एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार और संस्थाओं के आपसी समन्वय से ही दिल्ली को एक स्वच्छ और बेहतर राजधानी बनाया जा सकता है।

कपिल मिश्रा ने करावल नगर में गलियों के नवनिर्माण कार्य का किया शुभारंभ

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को करावल नगर विधानसभा में कालीघटा 20 फुटा रोड एवं अन्य गलियों के नवनिर्माण के काम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण 28 फुटा रोड का निर्माण कार्य भी एक माह के अंदर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 'विकसित करावल नगर' के लक्ष्य की दिशा में पूरे क्षेत्र का समग्र विकास हो रहा है, अब तक 300 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं।

इस अवसर पर कपिल मिश्रा ने करावल नगर विधानसभा के विकास कार्यों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बस सेवाओं में तीन गुना वृद्धि होनी है, करावल नगर डिपो, भगत सिंह कॉलोनी एवं चौहान पट्टी से कई नई ई बसों की शुरुआत होगी। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 आरोग्य मंदिर खोले जाने हैं, इनमें अब तक तीन का लोकार्पण हो चुका है। मंत्री ने बताया कि एक अन्य संकल्प 'अटल कैंटीन' भी दिल्ली में पूरा हो रहा है। गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए करावल नगर की पहली अटल कैंटीन की शुरुआत 20 फरवरी से पूर्व हो जाएगी। इसके बाद हर वार्ड में एक अटल कैंटीन शुरू करने का लक्ष्य है। उन्होंने ने कहा कि दिल्ली पुलिस की खाली भूमि पर एक बड़े और सुंदर पार्क के निर्माण की भी योजना है, आवश्यक स्वीकृतियों के बाद इसे वर्ष 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुकुंद विहार में गलियों का निर्माण जल्द शुरू होगा एवं अंकुर एन्क्लेव की शेष गलियों का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। साथ ही प्रमुख मार्ग खजूरी-भजनपुरा-दयालपुर-करावल नगर-शिव विहार के निर्माण व चौड़ीकरण का कार्य भी जल्द शुरू होगा।

मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल से अधूरी पड़ी सीवर लाइन के कार्य भी अब पूरे होंगे। खजूरी से सीवर लाइन की सफाई का कार्य शुरू हो गया है, अगले 3 से 4 माह में सीवर लाइनें शुरू हो जाएंगी। साथ ही हर गली में पक्की सड़क और लंबे समय से उपेक्षित सभी पंचायत घर और बारात घर के रेनोवेशन का कार्य भी होगा।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी

नई दिल्ली। राजधानी में बम की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को दिल्ली सचिवालय में बम की धमकी मिलने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत तत्काल मोर्चा संभाल लिया और पूरे परिसर को घेरकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। धमकी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ फायर विभाग, बम निरोधक दस्ता (बीडीएस), डॉग स्क्वॉड और अन्य संबंधित यूनिट की टीमें मौके पर पहुंचीं। घंटों चली गहन जांच के दौरान सचिवालय परिसर के हर हिस्से की बारीकी से तलाशी ली गई। हालांकि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बाद धमकी को झूठा यानी हॉक्स करार दिया गया। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बम की धमकी से जुड़ी कॉल सुबह 11 बजकर 24 मिनट पर उनके कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट किया गया और कुछ ही देर में टीमें मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा कारणों से परिसर में मौजूद कर्मचारियों और आगंतुकों को सतर्क किया गया और जांच पूरी होने तक आवाजाही सीमित कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कॉल करने वाले की पहचान के लिए तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में दिल्ली के विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश जांच के बाद फर्जी पाई गई हैं। इसके बावजूद हर धमकी को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रही हैं।

छत पर धूप में बैठा था परिवार, गहने-नकद उड़ा ले गए चोर

नई दिल्ली। खजूरी खास इलाके में दिनदहाड़े चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। आरोपी लाखों के गहने और नगदी लेकर फरार हो गए। ठंड से बचने के लिए परिवार के सभी सदस्य छत पर धूप में बैठकर चाय पी रहे थे, इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। करीब 20 मिनट के भीतर चोर मुख्य दरवाजे और आलमारी के ताले तोड़कर लाखों रुपये के गहने और 73 हजार रुपये से अधिक राशि लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित जमील अपने परिवार के साथ श्रीराम कॉलोनी में ई-ब्लॉक के मकान नंबर 441 में रहते हैं। एक फरवरी दोपहर करीब तीन बजे पूरा परिवार एक रिश्तेदार के साथ छत पर बैठा था। नीचे सभी कमरों में ताले लगे हुए थे। करीब 3:20 बजे जब परिवार वापस नीचे आया तो मुख्य गेट का कुंडा टूटा मिला।

कालकाजी हादसे में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता

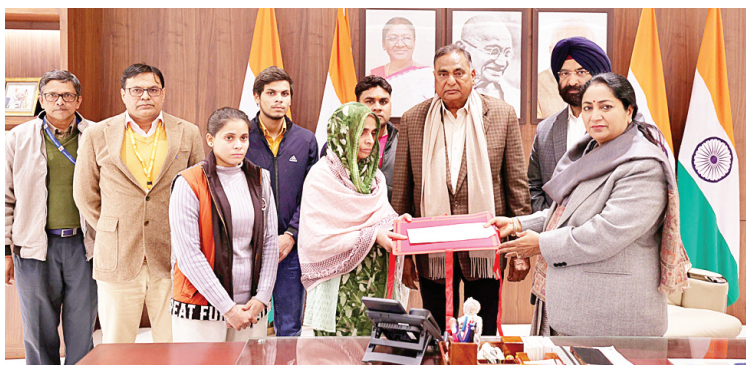

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में पिछले वर्ष पेड़ गिरने से हुई दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले सुधीर कुमार के परिजनों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का चेक सौंपा।

इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के इस मानवीय कदम के लिए आभार जताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृतक की पत्नी सुनीता देवी को विधवा पेंशन उपलब्ध कराई जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। उल्लेखनीय है कि यह हादसा भारी बारिश के दौरान हंसराज सेठी मार्ग पर हुआ था, जब एक बड़ा पेड़ बाइक सवार सुधीर कुमार पर गिर गया था, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और उनकी बेटी भी घायल हुई थी।

कांग्रेस ने की लापता बच्चों के मामलों पर टास्क फोर्स की मांग

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने राजधानी में छोटे बच्चों, विशेषकर लड़कियों के बड़ी संख्या में लापता होने की घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है।

उन्होंने इन मामलों की गंभीरता से जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग की है। देवेन्द्र यादव ने बताया कि वर्ष 2026 के पहले 27 दिनों में ही दिल्ली से 807 लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे, किशोरियां और महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन औसतन 27 लोगों के गायब होने के बावजूद न तो दिल्ली सरकार और न ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है, जो बेहद चिंताजनक है।

उन्होंने राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हत्या, बलात्कार, लूटपाट, जबरन वसूली और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। यादव ने पिछले वर्ष के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में हत्याएं, हत्या के प्रयास, बलात्कार और महिलाओं से जुड़े अपराध यह साबित करते हैं कि पुलिस व्यवस्था आम जनता को सुरक्षा देने में विफल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर केंद्र सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे नारों का प्रचार करती है, वहीं देश की राजधानी में ही लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो उनके शिक्षा और भविष्य की बात करना केवल नारा बनकर रह जाएगा। देवेन्द्र यादव ने जोर देकर कहा कि अधिकतर लापता होने की घटनाएं गरीब परिवारों से जुड़ी हैं और मौजूदा हालात में एक मजबूत जांच तंत्र की सख्त जरूरत है। इसी उद्देश्य से उन्होंने टास्क फोर्स के गठन की मांग की है ताकि राजधानी में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बहाल हो।

दिल्ली के विकास को तेज करेगा केंद्रीय बजट : सिरसा

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के कैबिनेट मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 एक दूरदर्शी और जनहितैषी बजट है, जो दिल्ली के विकास को तेज करेगा और समाज के हर वर्ग को मजबूत बनाएगा। मंत्री सिरसा ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह बजट 'विकसित भारत @2047' के संकल्प को आगे बढ़ाता है और दिल्ली के लोगों को सीधे लाभ पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट दिल्ली के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने वाला है। यह किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, उद्यमियों और व्यापारियों सभी के जीवन को सशक्त करेगा। मंत्री ने बताया कि बजट में किसानों की आय दोगुनी करने पर खास ध्यान दिया गया है। महिला किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बाजार से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारत-विस्तार एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार तुरंत सलाह मिलेगी, जिससे उत्पादन और आय दोनों में सुधार होगा। महिलाओं के लिए बजट को महत्वपूर्ण बताते हुए सिरसा ने कहा कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और लगभग 5 लाख करोड़ रुपये महिलाओं के लिए तय किए गए हैं। लखपति दीदी 2.0 के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का बिना गारंटी ऋण मिलेगा ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बहनें और बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी और आगे बढ़ेंगी। महिलाओं के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 'शे मार्ट' भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में बजट में 300 नए स्किल सेंटर और 19 नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रावधान किया गया है, इसके लिए बजट में करीब 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8.27 प्रतिशत अधिक है। इसमें पांच नए विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना भी शामिल है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार योग्य कौशल मिलेगा। सिरसा ने बताया कि दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बजट में घोषित सात नए रेल कॉरिडोरों में शामिल है। इससे यात्रा आसान होगी और प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने 'कैंसर जागरूकता रोकथाम और स्क्रीनिंग कार्यक्रम का किया शुभारंभ

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (डीएससीआई) की पहल 'कैंसर जागरूकता, रोकथाम और स्क्रीनिंग कार्यक्रम (सीएपीएस) का शुभारंभ किया। इसका मकसद राजधानी दिल्ली में कैंसर का जल्दी से पता लगाने, रोकथाम और आसानी से मिलने वाली कैंसर देखभाल सेवाओं को और ज्यादा मजबूत करना है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्स, टेक्नीशियन और हेल्थकेयर स्टाफ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. पंकज सिंह ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कैंसर के बढ़ते मामले को काबू करने के लिए समय पर स्क्रीनिंग और जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेहतर हेल्थकेयर सुविधाओं के कारण पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, इसलिए यहां ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट दर्ज होती है, जबकि देरी से टेस्टिंग होने से कैंसर जोखिम को और बढ़ाता है।

सीएपीएस पहल के तहत हमारी सरकार कम्युनिटी-बेस्ड तरीका अपना रही है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए कैंसर स्क्रीनिंग को सुलभ और रेगुलर बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। खास तौर पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन, जिनमें मैमोग्राफी और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था होगी को पहले से बताई गई प्रमुख जगहों और राजधानी के दूर-दराज के इलाकों में तैनात किया जाएगा ताकि दिल्ली के नागरिक अपने रोजाना के शेड्यूल को डिस्टर्ब किए बिना अपनी स्क्रीनिंग करवा सकें।

कार्यक्रम के दौरान सुविधाजनक और प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए एक सेल्फ-टेस्टिंग किट भी लॉन्च की गई। इस किट के माध्यम से महिलाएं खुद ही वैजाइनल स्वैब सैंपल लेकर लेबल युक्त वायल में सुरक्षित रख सकेंगी, जिसका एचपीवी डीएनए टेस्टिंग आरटी-पीसीआर तकनीक के जरिए किया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट एक हफ़्ते के भीतर शेयर की जाएंगी, जिसके बाद मेडिकल सलाह के साथ जरूरत पड़ने पर जरूरी इलाज भी बताया जाएगा। मैमोग्राफी रिपोर्ट के नतीजों को तुरंत एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही जिन महिलाओं को इलाज की जरूरत होगी, उनके लिए जरूरी फॉलो-अप केयर भी सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके अलावा कैंसर जागरूकता, कैंसर का जल्दी पता लगाने के तरीकों, तंबाकू विरोधी जागरूकता अभियान और भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की सुविधा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पंकज कुमार सिंह ने कहा कि कैंसर की रोकथाम हमारे प्रधानमंत्री का एक प्रमुख विजन है और हमारी मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। वर्तमान में हमारा विशेष फोकस कैंसर जागरूकता पर है, क्योंकि कई मरीज टेस्ट के लिए बहुत देर से आते हैं, जिससे इलाज बेहद मुश्किल हो जाता है।

दिव्य धाम आश्रम में मासिक आध्यात्मिक कार्यक्रम सम्पन्न

ध्यान, सेवा और गुरु उपदेशों पर चलने का लिया सामूहिक संकल्प

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान (डीजेजेएस) द्वारा दिव्य धाम आश्रम, दिल्ली में मासिक आध्यात्मिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्थापक एवं संचालक दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की समाधि के बारह वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुरु की शाश्वत आध्यात्मिक उपस्थिति का स्मरण करना तथा पूर्ण गुरु के प्रति निःस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना को जागृत करना रहा।

कार्यक्रम में दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु, शिष्य और साधक शामिल हुए। सत्संग की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना और भजनों से हुई, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। डीजेजेएस के प्रवक्ताओं ने 'गुरु प्रेम' विषय पर प्रेरक प्रवचन देते हुए बताया कि गुरु प्रेम केवल भावनात्मक लगाव नहीं, बल्कि आत्म-परिवर्तन की शक्ति है, जो साधक के अहंकार को समाप्त कर उसे दिव्य उद्देश्य से जोड़ती है।

उन्होंने कहा कि गुरु के प्रति समर्पण आत्म-साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है।इस अवसर पर दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की समाधि के बारह वर्ष पूर्ण होने का भावपूर्ण स्मरण किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि समाधि अंत नहीं, बल्कि गुरु की शाश्वत उपस्थिति और निरंतर मार्गदर्शन का प्रतीक है।कार्यक्रम का विशेष आकर्षण स्वयंसेवकों द्वारा प्रस्तुत सूफी संत बुल्ले शाह के जीवन पर आधारित भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति रही, जिसमें गुरु के प्रति निःशर्त प्रेम और समर्पण का संदेश प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। अंत में आयोजित निर्देशित ध्यान सत्र में श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की और सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे नियमित ध्यानाभ्यास, निःस्वार्थ सेवा और गुरु उपदेशों का पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन पथ पर अग्रसर रहेंगे।

मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर करते थे चोरी, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर भीड़ वाले इलाके में चोरियां करने वाले गिरोह का कोतवाली थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान राजगढ़, मध्य प्रदेश निवासी प्रीति (30), अनमोल (26)और सन्नो (32) के रूप में हुई है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। तीनों 28 जनवरी को कोतवाली इलाके में हाई कोर्ट की महिला वकील से लाखों रुपये के सोने-हीरे के जेवरात चोरी कर लिए थे। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों को मयूर विहार से दबोचा है। उत्तरी जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुमित कुमार झा ने बताया कि 28 जनवरी को एस. गर्ग नामक महिला वकील ने जेवरात चोरी की एक शिकायत दी थी। पीड़िता ने बताया कि वह अपने सोने और हीरे के जेवरात को मरम्मत करवाने के लिए किनारी बाजार, चांदनी चौक लेकर आई थीं। इस बीच किसी ने उनके बैग से जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की।

संपादकीय

अमेरिकन ट्रेड डील पर कूटनीतिक जीत

भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक बैकफुट पर जा पहुंचे? वही ट्रंप, जो टैरिफ को दुनिया को झुकाने का सबसे बड़ा हथियार बता रहे थे। ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को सीधे 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया। ताजा घटनाक्रम में चौंकाने वाली बात यह है कि टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप टस से मस होने को तैयार नहीं थे। हालिया बयान में ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के बाद टैरिफ घटाने की घोषणा की है। यहां यह सवाल उठना लाजिमी है कि वह क्या रहस्य है जिसने ट्रंप को अपना अटल इरादा बदलने को मजबूर कर दिया। शुरूआत में ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। इसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर कुल 50 फीसदी टैरिफ थोप कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत न तो झुका और न ही ट्रंप की शर्तों को स्वीकार किया। झुकना आखिर ट्रंप को ही पड़ा। कूटनीतिक मोर्चे पर यह भारत की बड़ी जीत मानी जा सकती है। ट्रंप के बैकफुट पर जाने की वजह प्रधानमंत्री के हालिया निर्णयों में देखी जा सकती है। 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के संगठन के साथ अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड अनुबंध किया। जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' बताया गया। इस कदम के बाद ट्रंप ने भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील टैरिफ में कटौती की घोषणा कर दी। ट्रेड डील के नाम पर ट्रंप की हठधर्मिता के सामने भारत ने सीधे टकराव के बजाए कूटनीतिक रास्ता चुना। भारत ने अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजार खोज लिए। यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील, ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ समझौतों ने अमेरिका के सामने अप्रत्याशित चुनौती पेश कर दी। जिससे ट्रंप को यह समझ आ गया कि भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर बड़ी भूल थी। बहरहाल भारत ने टकराव के बजाय धैर्य, कूटनीति और वैकल्पिक बाजारों की जो रणनीति अपनाई उसका नतीजा सामने है। यही वजह है कि टैरिफ वॉर में आखिरकार ट्रंप को ही बैकफुट पर आना पड़ा। यहां यह भी गौरतलब है कि टैरिफ वॉर से अमेरिकी जनता को भी नुकसान हो रहा था। भारत से अमेरिका को लगभग 129 अरब डॉलर का निर्यात होता है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी जनता को ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहां के बाजार में भी सामान महंगा हो गया था।

मणिपुर में खेमचंद सिंह की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा

हिंसा के चलते राज्य का प्रशासन लगभग पंगु हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन बाधित हुआ, कई महीनों तक इंटरनेट बंद रहा और व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ गई। अनुमान है कि इस संकट से मणिपुर की अर्थव्यवस्था को करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पर्यटन उद्योग पूरी तरह रुक गया और छोटे व्यापारियों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा। स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई, क्योंकि कई जिलों में डॉक्टरों और दवाइयों की आपूर्ति बाधित रही। शिक्षा का हाल यह रहा कि हजारों बच्चों की पढ़ाई महीनों तक बंद रही और कई स्कूल राहत शिविरों में बदल दिए गए। इसी हालात में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर कुकी समुदाय ने पक्षपात का आरोप लगाया। धीरे-धीरे बीजेपी के भीतर भी असंतोष बढ़ा। अक्टूबर 2024 में पार्टी के करीब डेढ़ दर्जन विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री बदलने की मांग की। दबाव इतना बढ़ा कि फरवरी 2025 में बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति शासन एक साल से ज्यादा नहीं चल सकता, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर यह मजबूरी बन गई कि नई सरकार का गठन किया जाए।

अजय कुमार

करीब एक साल तक राष्ट्रपति शासन में रहने के बाद मणिपुर में फिर से चुनी हुई सरकार बनने जा रही है और इस बार सत्ता की कमान युमनाम खेमचंद सिंह के हाथों में होगी। यह बदलाव सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि उस राज्य के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जो मई 2023 से जातीय हिंसा, विस्थापन और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुआ संघर्ष धीरे-धीरे इतना गहरा हो गया कि पूरा राज्य घाटी और पहाड़ के दो हिस्सों में बंटता दिखने लगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, 60 हजार से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और करीब 350 गांवों में सामान्य जीवन ठप हो गया। हजारों घर, स्कूल, चर्च और मंदिर जला दिए गए, जिससे सामाजिक ढांचा ही नहीं, आर्थिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हुईं।

हिंसा के चलते राज्य का प्रशासन लगभग पंगु हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन बाधित हुआ, कई महीनों तक इंटरनेट बंद रहा और व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ गईं। अनुमान है कि इस संकट से मणिपुर की अर्थव्यवस्था को करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पर्यटन उद्योग पूरी तरह रुक गया और छोटे व्यापारियों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा। स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुईं, क्योंकि कई जिलों में डॉक्टरों और दवाइयों की आपूर्ति बाधित रही। शिक्षा का हाल यह रहा कि हजारों बच्चों की पढ़ाई महीनों तक बंद रही और कई स्कूल राहत शिविरों में बदल दिए गए। इसी हालात में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर कुकी समुदाय ने पक्षपात का आरोप लगाया। धीरे-धीरे बीजेपी के भीतर भी असंतोष बढ़ा। अक्टूबर 2024 में पार्टी के करीब डेढ़ दर्जन विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री बदलने की मांग की। दबाव इतना बढ़ा कि फरवरी 2025 में बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति शासन एक साल से ज्यादा नहीं चल सकता, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर यह मजबूरी बन गई कि नई सरकार का गठन किया जाए।

इसी राजनीतिक और संवैधानिक दबाव के बीच युमनाम खेमचंद सिंह का नाम सामने आया। खेमचंद सिंह का चयन केवल पार्टी के भीतर संतुलन साधने का फैसला नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया गया कदम माना जा रहा है। वे मैतेई समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी मणिपुर में करीब 53 प्रतिशत है, लेकिन उन्हें कुकी और नागा समुदायों के बीच भी स्वीकार्यता वाला नेता माना जाता है। हिंसा के दौरान वे उन गिने-चुने मैतेई नेताओं में थे, जिन्होंने कुकी राहत शिविरों का दौरा किया और विस्थापित परिवारों से मुलाकात की। नागा बहुल उखरुल जिले में कुकी गांव के राहत शिविर में उनकी मौजूदगी को मानवीय संदेश के तौर पर देखा गया। उस समय जब घाटी और पहाड़ के बीच भरोसे की दीवार सबसे ऊंची थी, खेमचंद की यह पहल एक अलग संकेत थी कि वे केवल अपनी जाति की राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीतिक अनुभव के लिहाज से भी खेमचंद सिंह को मजबूत दावेदार माना गया। वे 2017 और 2022 में सिंगजामेई सीट से विधायक चुने गए। 2017 में पहली बार सत्ता में आने पर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने पूरे पांच साल सदन की कार्यवाही संभाली। 2022 में वे मंत्री बने और ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगर प्रशासन, आवास और शिक्षा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी निभाई। मणिपुर की राजनीति में करीब दो दशक से सक्रिय रहने वाले खेमचंद को संगठन और प्रशासन दोनों की समझ रखने वाला नेता माना जाता है। पार्टी नेतृत्व को लगा कि संकट के दौर में एक ऐसा चेहरा जरूरी है, जो अनुभव के साथ-साथ अपेक्षाकृत विवाद रहित भी हो।

मणिपुर विधानसभा का अंकगणित भी इस फैसले को मजबूती देता है। 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास फिलहाल 37 विधायक हैं। 2022 के चुनाव में पार्टी को 32 सीटें मिली थीं, लेकिन बाद में जेडीयू के पांच विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। एक सीट फिलहाल रिक्त है। इसके अलावा एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और 3 निर्दलीय विधायक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह एनडीए के पास कुल 46 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्ष 14 पर सिमटा है। संख्या के लिहाज से सरकार मजबूत है, लेकिन मणिपुर की राजनीति में असली चुनौती बहुमत नहीं, सामाजिक भरोसा है।

राज्य में आज भी करीब 50 हजार लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक केवल 25 से 30 प्रतिशत विस्थापित परिवार ही स्थायी रूप से अपने घर लौट पाए हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना लोगों का आना-जाना संभव नहीं है। सबसे बड़ी चिंता अवैध हथियारों की है। नई सरकार के सामने प्राथमिक चुनौती पुनर्वास और सुरक्षा की होगी। हजारों परिवार जिनके घर जल गए, उनके लिए स्थायी आवास, मुआवजा और रोजगार की व्यवस्था करना आसान काम नहीं है। केंद्र सरकार ने पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज देने की बात कही है, लेकिन जमीन पर इसका असर तभी दिखेगा, जब प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करे। स्वास्थ्य और शिक्षा को भी दोबारा पटरी पर लाना होगा। आंकड़ों के मुताबिक हिंसा के कारण 100 से ज्यादा स्कूल और दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र आंशिक या पूरी तरह बंद हो गए थे। इन्हें दोबारा चालू करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होगी। बीजेपी की रणनीति यह भी मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय से होंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री पद पर कुकी और नागा समुदाय से प्रतिनिधित्व देकर संतुलन बनाया जाएगा। यह फार्मूला सियासी तौर पर जरूरी है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना है। संवाद की प्रक्रिया शुरू करना, रास्ते खोलना, राहत शिविरों को धीरे-धीरे खाली कराना और प्रशासन पर भरोसा लौटाना सरकार की प्राथमिकता होगी।

खेमचंद सिंह की पृष्ठभूमि उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वे पेशे से ताइक्वांडो खिलाड़ी और शिक्षक रहे हैं। 1977 में उन्होंने इस खेल की शुरुआत की और करीब 20 साल तक सक्रिय खिलाड़ी रहे। दक्षिण कोरिया में प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय ताइक्वांडो टीम के कप्तान भी बने। बाद में वे खेल प्रशासक बने और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया में उपाध्यक्ष रहे। उनके समर्थक मानते हैं कि खेल से आई यही सोच उन्हें राजनीति में भी संतुलित बनाती है। खेमचंद सिंह को स्वच्छ छवि वाला नेता माना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री रहते हुए उन पर किसी बड़े भ्रष्टाचार या गंभीर विवाद का आरोप नहीं लगा। हिंसा के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से शांति की अपील की और कहा कि यह संघर्ष बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही बातें बीजेपी नेतृत्व को यह भरोसा दिलाती हैं कि वे सख्ती और संवेदना के बीच संतुलन बना सकते हैं। मणिपुर की राजनीति में यह संतुलन सबसे कठिन काम है, क्योंकि यहां मुद्दे केवल विकास या रोजगार तक सीमित नहीं, बल्कि पहचान, जमीन और अस्तित्व से जुड़े हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में अपेक्षाकृत शांति जरूर लौटी, लेकिन यह शांति प्रशासनिक नियंत्रण से बनी है, सामाजिक मेल-मिलाप से नहीं। नई सरकार के सामने असली चुनौती यही है कि वह लोगों के बीच भरोसा बहाल करे। अगर राहत शिविरों में रह रहे हजारों परिवार अपने घर लौटते हैं, बाजार फिर से खुलते हैं और बच्चे बिना डर के स्कूल जाते हैं, तभी यह माना जाएगा कि सरकार सफल हो रही है। मणिपुर की जनता अब भाषण नहीं, जमीन पर बदलाव देखना चाहती है।

युमनाम खेमचंद सिंह के लिए मुख्यमंत्री बनना केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक अग्निपरीक्षा है। उन्हें साबित करना होगा कि वे केवल पार्टी के नेता नहीं, पूरे राज्य के नेता हैं। लेकिन अगर अविश्वास और असुरक्षा की दीवारें जस की तस रहीं, तो यह सरकार भी उसी सवालों के घेरे में आ जाएगी, जिनसे बचने के लिए नेतृत्व बदला गया है। मणिपुर की राजनीति में अब असली लड़ाई सत्ता की नहीं, शांति और भरोसे की है, और इसी मोर्चे पर खेमचंद सिंह की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है।

काला अध्याय है पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन विधेयक

-डॉ. प्रियंका सौरभ-

संवैधानिक संशोधन लोकतंत्र की आत्मा होते हैं, जो समय के साथ बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए ढांचे को लचीला बनाते हैं। लेकिन जब ये संशोधन सत्ता के संतुलन को बिगाड़ने का हथियार बन जाते हैं, तो वे लोकतंत्र को ही खोखला करने लगते हैं। पाकिस्तान की संसद द्वारा नवंबर 2025 में पारित 27वां संवैधानिक संशोधन ठीक ऐसा ही एक उदाहरण है। यह संशोधन सतह पर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में कार्यपालिका और सेना के हाथों में न्यायपालिका को बंधक बनाने का प्रयास है। इसने न केवल पाकिस्तानी संस्थानों के बीच शक्ति संतुलन को उलट दिया है, बल्कि विधि के शासन को गंभीर खतरे में डाल दिया है। भारत जैसे पड़ोसी देश के लिए यह एक कठोर चेतावनी है, जहां न्यायिक स्वायत्तता लोकतंत्र की रीढ़ बनी हुई है। पाकिस्तान का यह कदम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी अपनी व्यवस्था ऐसी चुनौतियों के प्रति सजग है।

पाकिस्तान के संवैधानिक इतिहास को देखें तो संशोधन हमेशा से सत्ता संघर्ष का मैदान रहे हैं। 1973 के संविधान के बाद से 26 संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कई तानाशाही शासकों ने अपनी सनक के अनुरूप ढाले। लेकिन 27वां संशोधन एक नया मोड़ लाता है। इसमें संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना की गई है, जो संवैधानिक व्याख्या और मौलिक अधिकारों पर विशेष अधिकार क्षेत्र रखेगा। पहले ये जिम्मेदारियां सर्वोच्च न्यायालय के पास थीं। अब सर्वोच्च न्यायालय केवल गैर-संवैधानिक मामलों का अपीलीय निकाय बनकर रह गया है। यह बदलाव न्यायपालिका को उसके मूल कर्तव्य से वंचित करता है—संविधान का संरक्षक बनना। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर इस नए न्यायालय के जजों की नियुक्ति का अधिकार मिला है, बिना किसी पारदर्शी चयन मानदंड के। इससे राजनीतिक संरक्षण संस्थागत हो जाता है, जहां जजों की नियुक्ति सत्ता की कृपा पर निर्भर हो जाती है।

इसके अलावा, संशोधन उच्च न्यायालयों के जजों को उनकी सहमति के बिना प्रांतों के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। अगर कोई जज इनकार करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, यहां तक कि निष्कासन तक। यह प्रावधान न्यायाधीशों को कार्यपालिका के आगे झुकने पर मजबूर करता है। सबसे चिंताजनक सैन्य शक्ति का समेकन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया पद सृजित किया गया, जिसे सेना प्रमुख ही संभालेगा। इससे सेना को सभी सशस्त्र सेवाओं पर प्रधानता मिलती है और उसे अभियोजन से आजीवन छूट भी प्रदान की गई है। पाकिस्तान का यह हाइब्रिड शासन मॉडल अब संवैधानिक रूप धारण कर चुका है, जहां सेना सिविल प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप का औपचारिक आधार पा गई है। विधेयक को संसद में जल्दबाजी में पारित किया गया, बिना व्यापक बहस या विपक्षी परामर्श के। इससे संसदीय संप्रभुता ही कमजोर हुई है।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप न्यायिक संस्थाओं का विखंडन हो गया है। जवाबदेही का अभाव स्पष्ट है—राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को छूट देकर विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत तोड़ा गया। अब एक विशेष वर्ग कानून से परे हो गया है। असहमति को दबाने की प्रवृत्ति भी दिखी। वरिष्ठ जजों जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया, जो न्याय व्यवस्था में विश्वास की भारी कमी को दर्शाता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करने की क्षमता अब संदिग्ध है। विधि का शासन क्षरण की इस प्रक्रिया ने पाकिस्तान को एक ऐसे बिंदु पर ला खड़ा किया है, जहां लोकतंत्र केवल नाम का रह गया है। सैन्य हस्तक्षेप अब संवैधानिक वैधता के आवरण में हो रहा है।

भारत इस घटना से गहरी सीख ले सकता है। हमारा संविधान शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, और न्यायपालिका ने इसे बार-बार मजबूती दी है। केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित मूल ढांचा सिद्धांत संवैधानिक संशोधनों के विरुद्ध सबसे बड़ी ढाल है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संशोधन न्यायिक समीक्षा या शक्तियों के विभाजन को कमजोर न करे। पाकिस्तान का अनुभव बताता है कि कार्यपालिका के नेतृत्व वाली नियुक्तियों से बचना चाहिए। हमारी कॉलेजियम प्रणाली भले आलोचित हो, लेकिन यह बेंच को राजनीतिक आधिपत्य से बचाती है। जजों के तबादलों को पारदर्शी और प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित रखना जरूरी है, न कि दंडात्मक मंशा से प्रेरित। समानांतर न्यायालयों के निर्माण का कोई प्रस्ताव हो तो उसकी कठोर जांच होनी चाहिए, ताकि वे कार्यपालिका के हितैषी न बनें।

भारतीय बार और बेंच को एकजुट रहना चाहिए। विभाजित न्यायपालिका विधायी अतिक्रमण के प्रति कमजोर पड़ती है। संसदीय बहसों को मजबूत बनाना होगा, ताकि संशोधन जल्दबाजी में न पास हों। नागरिक समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है—सार्वजनिक विमर्श से सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारत ने अब तक 106 संशोधन झेले हैं, लेकिन मूल ढांचा अटल रहा। फिर भी, सजगता जरूरी है। राजनीतिक अस्थिरता या बहुमत की निरंकुशता में संशोधन सत्ता केंद्रीकरण का हथियार बन सकते हैं। न्यायिक स्वायत्तता केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि निरंतर संघर्ष है।

पाकिस्तान का 27वां संशोधन एक लोकतांत्रिक दुविधा है—जहां विधिक प्रक्रियाओं का उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के लिए हो रहा है। भारत को इस अनुभव से सतर्क होकर अपनी संस्थाओं को और मजबूत करना चाहिए। न्यायपालिका मनमानी सत्ता पर अंकुश बनी रहे, तभी गणराज्य की पवित्रता सुरक्षित रहेगी। समय है कि हम पाकिस्तान की गलतियों से बचें और लोकतंत्र को सशक्त बनाएं।

पाकिस्तान का 27वां संवैधानिक संशोधन लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय है। यह सतह पर प्रक्रियात्मक वैधता का दिखावा करता है, किंतु वास्तव में कार्यपालिका और सेना द्वारा न्यायपालिका पर कब्जे का प्रयास है। संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना, जजों की मनमानी नियुक्तियां, बिना सहमति तबादले और सैन्य छूट ने शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। विधि का शासन क्षरण, संस्थागत विखंडन और विश्वास-ह्रास ने पाकिस्तान को हाइब्रिड शासन की ओर धकेल दिया, जहां सिविल प्रक्रियाएं सैन्य छत्रछाया में सिकुड़ गईं। जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे इस्तीफों ने संकट की गहराई उजागर की। भारत के लिए यह कठोर अनुस्मारक है। मूल ढांचा सिद्धांत, कॉलेजियम प्रणाली और पारदर्शी तबादलों को अटल रखें। समानांतर न्यायालयों का प्रतिरोध करें, बार-बेंच एकजुट रहें। संसदीय बहसें मजबूत हों, नागरिक विमर्श सक्रिय। न्यायिक स्वायत्तता निरंतर संघर्ष है—इसे मजबूत रखें, ताकि मनमानी सत्ता पर अंकुश बना रहे। पाकिस्तानी दुविधा से बचकर भारत लोकतंत्र की मिसाल बने। गणराज्य की पवित्रता रक्षा ही हमारा कर्तव्य है।

सही ढंग से कार्य पूरा करना ही पूजा है

धर्मकर्म

प्रभु के चरणों में बैठ कर जिस तरह हम तल्लीन होकर एकाग्र होकर पूजा करते हैं। उसी तरह अपने कार्य को भी तल्लीन होकर पूर्ण ईमानदारी से करे तो वह किसी पूजा से कम नहीं होता। जिस तरह बेमन से पूजा करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार बेमन से कोई कार्य करने से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। सदकार्य करना, कार्य को पूर्ण मनोयोग से करना, कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित होना ही श्रेष्ठ पूजा है। अपने जीवनकोपार्जन में सदा उचित लाभ प्राप्त करना ही ईश्वर की पूजा के समान है। हक का कमाना तथा हक से उसका उपयोग करना ही मानव का प्रथम कर्तव्य है। तरह-तरह के लोग तरह-तरह से काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो काम की उलझनों और परेशानियों को बिना समझे-बूझे काम शुरू कर देंगे और फिर बिना योजना बनाये काम हाथ में ले लेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो एक साथ बहुत से कामों को अपने सिर पर लाद लेंगे और नतीजा यह होगा कि कोई भी काम संतोषजनक ढंग से नहीं हो पायेगा। कुछ लोग माथे का पसीना तक नहीं पोंछते और काम में लगे रहते हैं। अनेक ऐसे भी लोग हैं जो आसान-आसान कामों को पहले चुन लेते हैं और पेचीदा कामों को अगले दिन के लिये छोड़ देते हैं।

तरीके अलग-अलग- काम करने के तरीके और विधियां भी अलग-अलग होती हैं। औजार एक ही तरह के होते हैं। लेकिन एक अकुशल बढ़ई एक रद्दी सी बैंच ही तैयार कर पायेगा और अर्ध्द-कुशल एक अच्छी कुर्सी। लेकिन एक कुशल बढ़ई खूबसूरत और चमकती हुई कैबिनेट तैयार कर डालता है जो ग्राहकों का मन मोह लेती है। अब जरा सोचिये कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर में क्या अंतर है? जाहिर है कि काम करने की उत्तम कला कुशल मजदूर में निखर उठती है जबकि अकुशल मजदूर जोड़ तोड़ करके काम कर पाता है। हर काम करना एक कला है। नेतृत्व में एक कला है। विवाह में एक कला है। यहां तक कि वृध्द होने में भी एक कला है। तब फिर काम तो हमारे जीवन का स्थायी अंग है। उसमें कला का निखार क्यों न हो?

लक्ष्य तय करें- हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। बिना लक्ष्य के काम आगे नहीं बढ़ता। जब लक्ष्य सामने होता है तो हमारी तमाम शक्तियां उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाती हैं। काम अनेक तरह के होते हैं और उनकी समस्याएं भी अनेक होती हैं।

आज का इतिहास

1781 - बेनेडिक्ट अर्नोल्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना अभियान ने रिचमंड, वर्जीनिया को जला दिया।
1809 - यूनाइटेड किंगडम ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और ओटोमन साम्राज्य के बीच डारडेनेलेल की संधि हुई।
1827 - होबार्ट में नदी डेरवेंट पर तस्मानिया (उस समय स्वान डाइमेन की भूमि कहा जाता है) पर ऑस्ट्रेलिया में पहला रेगाटा आयोजित किया गया।
1889 - प्रेस्टन नॉर्थ एंड एफ सी को फुटबॉल लीग का विजेता घोषित होने पर इंग्लैंड में उद्घाटन किया गया।
1905 - चार्ल्स पेरीन ने बृहस्पति के सातवें उपग्रह इलारा की खोज की घोषणा की।
1909 - कोलंबिया ने पनामा की आजादी को स्वीकार किया।
1912 - प्राग के एक सम्मेलन में व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से अलग हो गई।
1914 - अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने पहली बार कर्मचारियों का एक दिन का भत्ता पांच डॉलर देने की सीमा निर्धारित करके दुनिया के सामने न्यूनतम वेतन का उदाहरण पेश किया।
1914 - फोर्ड मोटर कंपनी ने 5 की दैनिक मजदूरी के साथ आठ घंटे की कार्यदिवस की घोषणा की।
1919 - आयरलैंड के प्रसिद्ध नाविक अरनेस्ट हेनरी शेकलेटन का निधन हुआ।
1919 - जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी के अग्रदूत, एंटोन ड्रेक्सलर द्वारा स्थापित किया गया था।
1925 - नेली टायलो रॉस को व्योमिंग के गवर्नर के रूप में उद्घाटन किया गया था, जो अमेरिकी राज्य की राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी।
1935 - वॉल्ट डिज़नी ने एनिमेटेड लघु फिल्म द टर्टोइज़ एंड द हरे का उद्घाटन किया।
1939 - वाल्लिसिल की लड़ाई शुरू हुई।

आत्महत्या रोकथाम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाना समय की माँग

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी-

वैश्विक स्तरपर मानव सभ्यता की प्रगति के साथ-साथ मानसिक,सामाजिक और आर्थिक जटिलताएँ भी बढ़ती गई हैं। इन्हीं जटिलताओं से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय है,आत्महत्या। यह केवल किसी व्यक्ति का निजी निर्णय नहीं होता,बल्कि इसके पीछे सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों का गहरा प्रभाव होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तरपर आत्महत्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक माना जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार, हर साल लगभग 7 लाख लोग आत्महत्या करके अपनी जान गंवाते हैं, जिसका अर्थ है कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं,बल्कि वैश्विक संकट है। जिसका समाधान अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सम्मिट बुलाकर करना समय की मांग है। बता दे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है।यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10 पर्सेंट की कमी लाने के लिये समयबद्ध कार्य योजना और बहु-क्षेत्रीय सहयोग शामिल है। यह रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है।

साथियों बात अगर हम आत्महत्या क्या है और क्यों की जाती है? किस देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है?इसको समझने की करें तो, आत्महत्या का सामान्य अर्थ है, व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपनी जान लेना। यह निर्णय किसी क्षणिक आवेग का नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले मानसिक और सामाजिक दबाव का परिणाम होता है। डब्लूएचओ की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या करने वालों में से लगभग 77 पर्सेंट लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों से होते हैं,जहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित होती हैं और सामाजिक कलंक के कारण लोग मदद माँगने से कतराते हैं। आत्महत्या के मुख्य कारणों में डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, नशे की लत, तथा सामाजिक अलगाव प्रमुख हैं। इसके अलावा रिश्तों में असफलता, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, घरेलू हिंसा और युवाओं पर शिक्षा व करियर का दबाव भी आत्महत्या के प्रमुख कारक हैं।वैश्विक स्तर परआत्महत्या की दर हर देश में अलग-अलग है।डब्ल्यूएचओ की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि लिथुआनिया दक्षिण कोरिया,रूस, गुयाना और जापान जैसे देशों में प्रति 1 लाख आबादी पर आत्महत्या दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, लिथुआनिया में यह दर लगभग 25.7 प्रति 1 लाख है, जबकि दक्षिण कोरिया में लगभग 20.2 प्रति 1 लाख। वहीं भारत और चीन जैसे देशों में कुल आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है,क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी है। भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरब) 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, एक साल में 1.64 लाख से अधिक आत्महत्याएँ दर्ज की गईं, यानें हर दिन औसतन 450 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या दैनिक वेतन बोगियों, छात्रों और किसानों की है। जापान में आत्महत्या लंबे समय से सामाजिक समस्या रही है,जहाँ हर साल लगभग 20,000 से अधिक लोग जीवन समाप्त कर लेते हैं।

साथियों बात अगर हम आत्महत्या केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक चुनौती होने की करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि आत्महत्या को केवल व्यक्तिगत समस्या मानना उचित नहीं है।डब्ल्यूएचओ और अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ (आईएएसपी) के विशेषज्ञ मानते हैंकि आत्महत्या दरअसल मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का परिणाम है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के पीछे गरीबी, सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव और शिक्षा का अभाव जैसी समस्याएँ भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। युवाओं मेंआत्महत्या की दर विशेष रूप से चिंताजनक है। 15-29 वर्ष आयु वर्ग में आत्महत्या मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। डिजिटल युग में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन दबाव और सोशल मीडिया की अवास्तविक अपेक्षाएँ भी युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल रही हैं।

साथियों बात अगर हम आत्महत्या रोकने के उपायों की करें तो शोध और डेटा संग्रह आत्महत्या रोकथाम की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। डब्लूयूएचओ की मेन्टल हेल्थ अटलस 2020 रिपोर्ट बताती है कि दुनियाँ के 80 पर्सेंट से अधिक देशों में आत्महत्या से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है या अधूरा है। इससे नीतियों का निर्माण कठिन हो जाता है। आईएएसपी लगातार इस दिशा में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने आत्महत्या रोकथाम पर व्यापक शोध किया है, जिससे यह साबित हुआ है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (सीबीटी), साइकोसोशल सपोर्ट, हेल्पलाइन सेवाएँ और सामुदायिक सहयोग आत्महत्या रोकने में बहुत प्रभावी हैं। पेशेवरों को प्रशिक्षित करना भी इस दिशा में अत्यंत आवश्यक है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाँ भर में प्रति 1 लाख लोगों पर औसतन केवल 13 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हैं, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात बहुत अधिक है। इस असमानता के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आत्महत्या रोकथाम चुनौतीपूर्ण बन जाती है। यदि डॉक्टर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आत्महत्या के संकेतों को पहचानने और सही समय पर हस्तक्षेप करने में प्रशिक्षित हों, तो कई जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। साथियों बात अगर हम आत्महत्याओं को रोकने के लिए शिक्षा और संवाद की आवश्यकता सबसे मजबूत हथियार होने की करें तो, आईएएसपी और डब्लूयूएचओ दोनों ही यह मानते हैं कि सार्वजनिक जागरूकता से आत्महत्या की प्रवृत्ति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डब्लूयूएचओ की 2022 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य पर संवाद बढ़ाने से आत्महत्या दर में 20 पर्सेंट तक की कमी लाई जा सकती है। आज भी अधिकांश समाजों में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या को लेकर सामाजिक कलंक मौजूद है। लोग इस विषय पर बात करने से कतराते हैं।

इसका परिणाम यह होता है कि पीड़ित व्यक्ति अकेलेपन और शर्मिंदगी का शिकार हो जाता है। युवाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना और उन्हें यह समझाना कि मदद माँगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है,अत्यंत आवश्यक है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग सेवाएँ, हेल्पलाइन नंबर, मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएँ शुरू करना उपयोगी साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया और जापान ने स्कूल स्तरपरमानसिक स्वास्थ्य शिक्षा लागू की है, जिससे आत्महत्या की दर कम करने में मदद मिली है। साथियों बात अगर हम आत्महत्या की रोकथाम के वैज्ञानिक और सामाजिक उपायों की करें तो,आत्महत्या रोकथाम के लिए बहुआयामी उपाय आवश्यक हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा साई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर-7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 **संपादक - आदित्य वशिष्ठ** कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@gmail. Com

राष्ट्रपति का अभिभाषण परंपरा और प्रगति का संगम : जेपी नड्डा

नई दिल्ली। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर बुधवार को चर्चा जारी रखते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का ज़िक्र कर उन्होंने कहा कि सरकार इसपर भी चर्चा के लिए तैयार है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अस्वस्थ होने के बावजूद मुंबई से दिल्ली आए, ताकि लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान दे सकें लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाने के कारण उनका भाषण नहीं हो सका। उन्होंने दावा किया कि भारत–अमेरिका व्यापार समझौता संतुलित है और देशहित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का नजरिया संकीर्ण है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत की परंपराओं के साथ-साथ विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप पेश करता है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की अद्भुत विकास यात्रा का शक्तिशाली प्रतिबिंब हमें देखने को मिला है। हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के साथ ही वर्ष-2047 के विकसित भारत का समावेश राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया है। उन्होंने कहा कि देश ने लंबा सफर तय किया है और प्रगति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम पहले किस स्थिति में थे। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत कभी "फ्रैजाइल फाइव" देशों में गिना जाता था, लेकिन आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश नीतिगत जड़ता (पॉलिसी पैरालिसिस) से निकलकर अब रिफॉर्म, परफॉर्म और परिवर्तन आये है। वर्ष-2025 में आये जीएसटी 2.0 से भारत के आर्थिक विकास में तेजी आई है। पिछला सप्ताह भारत की आर्थिक क्रांति के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रहा। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। वहीं भारतीय -ईयू व्यापार समझौते के बाद भारत और अमरिका व्यापार समझौता देश के आर्थिक विकास में ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबी हटाने की बात की लेकिन भ्रष्टाचार किया। गरीबों के नाम पर वोटबैंक लिया लेकिन गरीबों को बैंक तक नहीं जाने दिया।

गरीबों को शौचालय, पक्का आवास, पीएम-जनधन, उज्ज्वला योजना जैसी नीतियों से उन्हें कई अधिकार मोदी सरकार ने दिये हैं। मोदी सरकार में 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर निकलकर सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'आयुष्मान भारत' योजना के अंतर्गत 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये की इलाज की गारंटी दी गई है, ये योजना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है। कांग्रेस की सरकारों ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जेपी नड्डा ने कहा जब राष्ट्रपति जी अपना वक्तव्य दे रहीं थीं तो विपक्ष ने उनके अभिभाषण में व्यवधान करते हुए नारे लगाये थे।

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की दलीलें भले अच्छी लगें लेकिन ज़मीनी हकीकत इतनी खराब है कि उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। खरगे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई अहम मुद्दों पर चुप्पी रही। उन्होंने सदन के सामने सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले, अर्थव्यवस्था की स्थिति, किसानों और मजदूरों के संघर्ष तथा विदेश नीति की कमियों जैसे विषय उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को सिर्फ भाजपा का वोट बैंक बनाकर देखा जा रहा है। खरगे ने सरकार से सवाल किया कि महिलाओं को आरक्षण अब तक पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की कथनी और करनी के बीच के अंतर को दर्शाता है।

विपक्ष के हंगामे के बीच पीयूष गोयल ने लोकसभा में भारत-अमेरिका व्यापार डील पर दिया बयान

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच भारत-अमेरिका के बीच व्यापार डील पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश और निर्यातकों के हित में है और इसमें कृषि-खाद्य क्षेत्रों की संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के भारी शोर-शराबे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। गोयल के बयान के दौरान लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ जिस द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहा है, वह संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की पूरी तरह से रक्षा करता है। उन्होंने सदन को बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए बातचीत पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते से भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। गोयल ने लोकसभा में कहा कि दोनों देश जल्द ही समझौते का विवरण देते हुए एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि इस डील में उर्वरक और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि यह समझौता छोटे और मध्यम कारोबारियों, एमएसएमई, औद्योगिक इकाइयों, कुशल श्रमिकों और उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा एवं उन्नत तकनीकों तक पहुंच को आसान बनाएगा।

इससे 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड', 'डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' और 'इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्यों को गति मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के हितों को देखते हुए स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। गोयल ने कहा कि अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे, जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। उन्होंने कहा एक साल तक चली कई दौर के विचार विमर्श के बाद व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। यह समझौता विशेष रूप से श्रम प्रदान क्षेत्रों और विनिर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

संसद परिसर में राहुल गांधी-रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक

नई दिल्ली। संसद परिसर में बुधवार को उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व सहयोगी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया।

राहुल गांधी ने बिट्टू को 'गद्दार' कहा तो जवाब में बिट्टू ने उन्हें 'देश का दुश्मन' करार दिया। यह घटना संसद के मकर द्वार के बाहर हुई जहां कांग्रेस सांसदों के निलंबन के विरोध में पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी निलंबित कांग्रेस सांसदों, जिनमें अधिकांश पंजाब से थे, उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए मकर द्वार के पास खड़े थे। इसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे। प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए वीडियो के मुताबिक, राहुल गांधी ने बिट्टू को देखते हुए कहा कि देखो, एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है। इसका चेहरा देखो। इसके बाद उन्होंने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा कि नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे। हालांकि, रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और पलटवार करते हुए कहा कि देश के दुश्मन'। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी बातचीत होती दिखी। घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने पंजाब को आग में झोंक दिया था और गोल्डन टेंपल पर गोलियां चली थीं। उन्होंने कहा कि हजारों सिखों और पंजाबियों को निशाना बनाया गया। बिट्टू ने यह भी कहा कि जब तक वे कांग्रेस में थे, तब तक उन्हें शहीद का पोता कहा जाता था लेकिन भाजपा में आने के बाद उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को देश का मालिक समझते हैं और रोज सेना व राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं इसलिए उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया।

इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि एक सांसद और सम्मानित सिख नेता सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को 'गद्दार' कहना शिष्टाचार, मर्यादा और गरिमा की सभी सीमाओं को पार करता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी आधार के किसी प्रतिष्ठित सिख नेता को गद्दार कहना न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि पूरे सिख समुदाय का अपमान है। संसद परिसर में हुई इस नोकझोंक के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है और दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

राहुल गांधी ने संसद परिसर में नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक दिखलाते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा

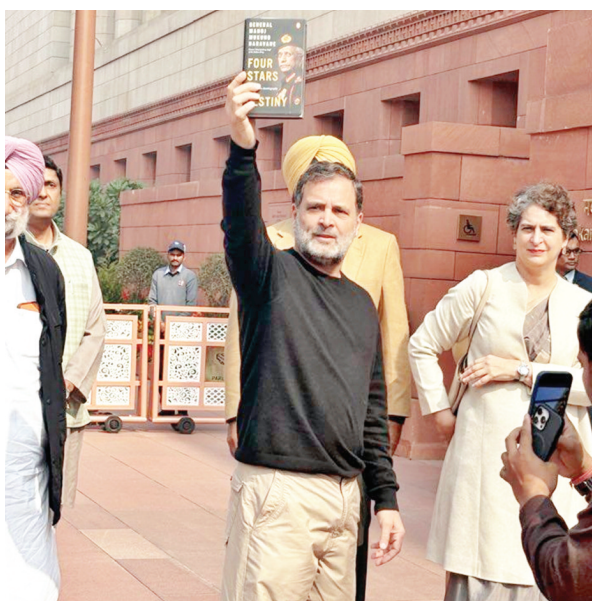

नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद के बाहर पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक दिखलाते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कथित तौर पर चीन के साथ साल 2020 में सैन्य तनातनी के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर पुस्तक में दिए विवरण को आधार बनाया और सरकार पर मुश्किल समय में सेना का साथ छोड़ने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी संसद के मकर द्वार के बाहर नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक की प्रति दिखलते हुए कहा कि भारत के हर युवा को यह किताब देखनी चाहिए। इसमें उन्होंने लद्दाख का पूरा ब्योरा दिया है। लोकसभा में उन्हें इसी किताब में कही बातों को रखने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कल पत्र लिखकर संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा उठाने के विपक्ष के नेता के अधिकार से वंचित किए जाने के संबंध में अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल का समर्थन करते हुए कहा कि भाषण देते समय वे अक्सर पुस्तकों से उद्धरण देते हैं। राहुल गांधी एक प्रकाशित स्त्रोत से उद्धृत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी संजय बारू को उद्धृत किया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें कहना चाहिए कि हमारे खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया जाए।

लोकसभा में बोलने की अनुमति न दिए जाने के आरोप में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पत्र पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उनको जवाब दिया गया है। वे नियमों के बाहर बोल रहे हैं। हमने दो दिन इंतजार किया लेकिन दूसरों को भी बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। वे मनमाने ढंग से नहीं बोल सकते। यह भारत की संसद है। इसी बीच कल अमर्यादित आचरण के कारण निलंबित सांसदों ने आज संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई।

गुलमर्ग और पहलगाम में रात का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया

श्रीनगर। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम के पर्यटक रिसॉर्ट्स में रात का तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे गिर गया जबकि घाटी के बाकी हिस्सों में गर्म रात का आनंद लिया गया।

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 8.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जो मंगलवार रात की तुलना में 2.7 डिग्री कम है। पहलगाम, दक्षिण कश्मीर में एक पर्यटन स्थल जो अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है का तापमान शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री कम होकर शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। श्रीनगर में मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसमी औसत से 3.6 डिग्री अधिक था।

रोहतक: विदेश मंत्रालय में नौकरी के नाम पर दस लाख की ठगी, मामला दर्ज

रोहतक। विदेश मंत्रालय में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से दस लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में पीडित युवक की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार लाखनमाजरा निवासी जितेन्द्र ने बताया कि वह बिजली का मिस्त्री है और उसकी बुआ का पोता मनदीप जो फौज से रिटायर होकर देहरादून स्थित एक कंपनी में नौकरी करता था और उसकी मुलाकात वहां विजय पॉल से हुई थी।

विजय ने जितेन्द्र को बताया कि उसकी दिल्ली में विदेश मंत्रालय में जान पहचान है और वह दस लाख रूपये में कार स्टॉफ ड्राइवर की सरकारी नौकरी लगवा सकता है। जितेन्द्र युवक की बातों में आ गया और उसे दस लाख रूपये दे दिए। पीडित ने आरोप लगाया कि विजय ने फर्जी ज्वाईन लेंटर भी दिया और विशाल, मेधा, महेन्द्र व मोहित बार बार उसके चक्कर भी कटवाते रहे। जितेन्द्र ने अपने साथ हुई ठगी का जब पता चला तो उसने आरोपियों से जब अपने पैसे वापिस मांगे, लेकिन अब आरोपी पैसे वापिस नहीं कर रहे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे है। पुलिस ने इस संबंध में नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चुनाव आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन 24 फरवरी को भारत मंडपम में

नई दिल्ली। चुनाव आयोग 24 फरवरी को यहां भारत मंडपम में राज्य निर्वाचन आयुक्तों (एसईसी) के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है जिसमें देश के सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) भाग लेंगे। पिछला ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था।

चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और उद्घाटन समारोह में राज्य निर्वाचन आयुक्तों को संबोधित करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी विशेषज्ञों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भाग लेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य अपने-अपने कानूनी ढाँचे के अंतर्गत चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों (एसईसी) के कामकाज में तालमेल स्थापित करना है। 6. प्रतिभागी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता पात्रता संबंधी चुनावी कानूनों, चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे हाल ही में लॉन्च किए गए ईसीआईएनईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म और ईवीएम आदि पर चर्चा सत्रों में भाग लेंगे। चुनाव आयोग भारत के संविधान और देश के कानूनी ढाँचे के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के अपने अनुभव से विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा। राज्य चुनाव आयोगों का गठन संबंधित राज्यों के कानून द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों के तहत किया गया है। एसईसी को पंचायतों और नगर निकायों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सौंपा गया है।

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

बिहार में बनेगा रक्षा गलियारा: सम्राट चौधरी

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि राज्य में रक्षा गलियारे का निर्माण कराया जाएगा जिससे न केवल राज्य की औद्योगिक क्षमता सुदृढ़ होगी, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

रक्षा मंत्रालय की ओर से अध्ययन दौरे पर बिहार आए राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी (एनडीए) के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों से उपमुख्यमंत्री की बुधवार को मुलाकात हुई। इस दौरान चौधरी और अधिकारियों के बीच बिहार में प्रस्तावित रक्षा गलियारे की योजनाओं, संभावनाओं और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सार्थक और विस्तृत चर्चा हुई। चौधरी ने कहा कि यह बैठक बिहार के औद्योगिक और सामरिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चौधरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े और उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिलें। इसी उद्देश्य से उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि गया जी जिले के डोभी क्षेत्र में एक विशाल औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है, जो आने वाले समय में राज्य के विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। चौधरी ने कहा कि इसके साथ ही राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पार्क की स्थापना तथा भागलपुर सहित अन्य स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। उनके मुताबिक, रक्षा गलियारे के निर्माण से बिहार रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 'डबल इंजन' की सरकार बिहार को उद्योग और रोजगार का केंद्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की अध्ययन टीम के साथ हुई यह बैठक उसी दिशा में एक ठोस पहल है।

तेलंगाना के मेदाराम जातरा में कथित यौन उत्पीड़न पर एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम में हाल ही में आयोजित सम्मक्का-सरलम्मा जातरा के दौरान 13 वर्षीय बालिका के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना का संज्ञान लिया है। यह घटना छत्तीसगढ़ के पांच युवकों द्वारा कथित रूप से किए गए सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस कथित घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। आयोग द्वारा बुधवार को जारी जानकारी के अनुसार जांच समिति की अध्यक्षता एनसीडब्ल्यू की सदस्य डेलिना खोंगदुप करेंगी। एनसीडब्ल्यू की वरिष्ठ समन्वयक कंचन खट्टर समिति की सदस्य होंगी। समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), मुलुगु, तेलंगाना द्वारा नामित एक अधिवक्ता की सहायता भी ले सकती है। समिति जांच की शुरुआत 5 फरवरी से करेगी।

समिति के सदस्य कथित घटना तक पहुंचने वाली परिस्थितियों की जांच, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन, तथ्यों की पुष्टि हेतु संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों से संवाद करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों की संस्तुति करने का दायित्व सौंपा गया है। जांच की बाद समिति अपनी संस्तुतियां आयोग को उपयुक्त कार्रवाई के लिए सौंपेगी। आयोग जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की सतत निगरानी करेगा।

मिथिला की कला-संस्कृति को मिलेगी वैश्विक पहचान, अयोध्या में बनेगी 'वैदेही आर्ट गैलरी'

मिथिला की संस्कृति, लोकपरंपरा और कला के विविध आयामों को गैलरी में प्रमुखता से दर्शाएं : सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीअयोध्या धाम में माता सीता के जीवन और आदर्शों पर केंद्रित एक विशेष 'वैदेही आर्ट गैलरी' की स्थापना के निर्देश दिए हैं। यह गैलरी भारतीय संस्कृति, मर्यादा, करुणा और नैतिक मूल्यों की अनुपम प्रतीक सीता माता के जीवन-चरित को आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री आवास पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि सीता मइया भारतीय सभ्यता की आत्मा हैं और उनका जीवन त्याग, धैर्य, साहस, करुणा और नारी शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है।

नई पीढ़ी को उनके चरित्र से गहराई से परिचित कराना आज के समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 'वैदेही आर्ट गैलरी' केवल एक पारंपरिक कला-संग्रहालय नहीं होगी, बल्कि यह एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव-स्थल के रूप में विकसित की जानी चाहिए। इसमें सीता माता के जीवन प्रसंगों का आधुनिक तकनीक, डिजिटल माध्यम, दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति और कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए पुनर्पाठ किया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिया कि गैलरी की कथा-वस्तु, डिजाइन, विजुअल भाषा, कला और तकनीकी प्रस्तुति इस भावना को प्रतिबिंबित करे कि यह एक दिव्य और शाश्वत विरासत है, जिसे भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत के रूप में संरक्षित और प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गैलरी की मूल अवधारणा यह होनी चाहिए कि आगंतुक सीता माता के जीवन-संदेश को केवल देखें ही नहीं, बल्कि उसे महसूस करें, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। गैलरी में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए, जिससे दर्शक भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ सकें। अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि यह परियोजना श्रीअयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निकट वरिष्ठ वशिष्ठ भवन परिसर में विकसित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही का केंद्र है, जिससे 'वैदेही आर्ट गैलरी' को व्यापक पहचान और वैश्विक मंच मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वैदेही आर्ट गैलरी' का निर्माण श्रीअयोध्या धाम को वैश्विक सांस्कृतिक नगर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। यह न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर और अधिक मजबूती से प्रस्तुत करेगा।

उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि गैलरी में मिथिला की संस्कृति, लोकपरंपराओं और कला के विविध आयामों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। मिथिला चित्रकला, लोककथाएं, परंपरागत संगीत और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से माता सीता के जीवन और उनकी भूमि की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाए। अंत में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि परियोजना की रूपरेखा, डिजाइन और क्रियान्वयन में गुणवत्ता, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि 'वैदेही आर्ट गैलरी' आने वाले समय में श्रद्धा, संस्कृति और प्रेरणा का प्रमुख केंद्र बन सके।

लंबित आवास मामलों के निस्तारण हेतु 'एकमुश्त समाधान योजना' लागू करें : मुख्यमंत्री योगी

- सभी पात्र आवंटियों तक ओटीएस योजना की जानकारी पहुंचे, मुख्यमंत्री ने व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक नई 'एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)' लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित देयों और विवादित मामलों के कारण न केवल योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था लागू करना है, जिसमें समाधान तेज, पारदर्शी और सभी के लिए व्यावहारिक हो।

अपने सरकारी आवास पर बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की किसी भी योजना में लंबित भुगतान या विवादित आवंटन राज्य की विकास गति को धीमा करते हैं। इसलिए आवास विभाग को ऐसी समाधान-प्रधान व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे विभाग को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो और आवंटियों को भी राहत मिले। उन्होंने कहा कि यह योजना जन-केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें हर वास्तविक आवंटी को स्पष्ट और सरल विकल्प उपलब्ध हों। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू की गई ओटीएस-2020 योजना से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ था लेकिन कोविड-19 के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर पाए। विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में प्रदेश के विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में मौजूद ऐसे सभी डिफॉल्ट मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओटीएस-2026 योजना को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी स्वरूप दिया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए। साथ ही, किस्तों में भुगतान की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों को अंतिम रूप देते समय यह ध्यान रहे कि योजना के मूल में आम आदमी को राहत देने का ही भाव निहित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभाग द्वारा प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना लागू होने से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को राजस्व भी प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे अवगत हो सकें। उन्होंने कहा, 'एकमुश्त समाधान योजना' के बारे में आम जनता के बीच सक्रिय रूप से जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि सभी पात्र लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि योजना की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए।

1694 आवेदकों को उद्योग शुरू करने में मिलेगा आर्थिक सहयोग

प्रयागराज। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रयागराज जिले को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1694 का लक्ष्य मिला है। इस योजना के तहत सरकार रोजगार प्रदान करने का अभियान चला रही है। इस योजना के तहत अनुदान का 35 प्रतिशत सरकार सब्सिडी दे रही है। यह जानकारी बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में अनुदान देने के मामले में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज प्रथम स्थान पर है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग, प्रयागराज ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत पी.एम.एफ.एम.ई. संचालित है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्योग को लाभान्वित कर कुशल और अकुशल रोजगार उत्पन्न करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में एक जिला एक उत्पाद की स्थापना एवं पूर्व से स्थापित अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ पात्र होगी। योजना के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 पास होना आवश्यक है। एक परिवार के केवल एक ही व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रयागराज को 1694 का लक्ष्य प्राप्त है। इस योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय तकनीकी और व्यवसायिक सहायता प्रदान की जाती है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए कुल लागत की 35 प्रतिशत तक क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाती है। आटा चक्की, तेल पेराई, धान कुटाई, बेकरी, डेयरी, जैम एवं जैली, अचार, मुरब्बा, कैन्डी एवं पापड़ जैसे सूक्ष्म उद्योग लगा सकते है।

एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात इनामी बनारसी यादव

वाराणसी। सारनाथ थाना क्षेत्र में कालोनाइजर महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या करने वाले इनामी शूटर बनारसी यादव को एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स)ने मुठभेड़ में ढ़ेर कर दिया। इस दौरान उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। मंगलवार की देर रात चौबेपुर थाना क्षेत्र के जाल्हूपुर रिंग रोड बरियासनपुर के पास हुई मुठभेड़ की जानकारी पाते ही अफसर भी मौके पर पहुंच गए। एक लाख रूपये के इनामी बदमाश की तलाश पुलिस टीम पिछले पॉच माह से कर रही थी।

एसटीएफ के अफसरों के अनुसार देर रात निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव और अनिल कुमार सिंह को सूचना मिली कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए दो इनामी शूटर बाइक से रिंग रोड की तरफ कुछ ही देर में आने वाले है। एसटीएफ के निरीक्षकों ने अपनी टीम के साथ रिंग रोड पर पहुंच कर घेरेबंदी कर ली। इसी दौरान गाजीपुर की तरफ से बाइक पर सवार दो युवक आते दिखे।

एसटीएफ टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसमें से एक ने गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश को लगी और वह जमीन पर चीख कर गिर पड़ा। यह देख उसकर साथी बाइक लेकर मौके से भाग निकला।

पुलिस टीम ने मुठभेड़ की जानकारी अफसरों को देने के साथ घायल बदमाश को तत्काल पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल पांडेयपुर पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत बदमाश की पहचान गाजीपुर गौरहट निवासी बनारसी यादव के रूप में हुई। कालोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के मामले में उसकी तलाश पुलिस को लम्बे समय से थी।

मुठभेड़ में ढ़ेर बदमाश के पास से दो पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ। बताते चले कालोनाइजर हत्याकांड में बनारसी के साथ रहने वाले सेना के जवान गाजीपुर महाराजगंज निवासी अरविंद यादव को एक महीने पहले पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। बीते 21 अगस्त को सारनाथ थाना क्षेत्र के सिंहपुर-अरिहंत नगर कालोनी में कालोनाइजर महेंद्र गौतम की बाइक सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक बदमाश बाइक चला रहा था, जब कि पीछे बैठे दो बदमाश गोलियां चला रहे थे।

गैंगस्टर रवि काना की रिहाई का मामला: बांदा जेल के निलंबित जेलर और अधीक्षक पर प्राथमिकी दर्ज

बांदा। नोएडा के कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर रविन्द्र सिंह उर्फ रवि काना की कथित तौर पर गैरकानूनी रिहाई के मामले में निलंबित बांदा जेल के जेलर और जेल अधीक्षक के विरुद्ध मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। बांदा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पलाश बंसल ने बताया कि जेल चौकी प्रभारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अपराधी रवि काना की रिहाई से संबंधित इस मामले में शहर कोतवाली में जेल अधीक्षक, जेलर और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, ''मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो इस बात की गहन पड़ताल कर रही है कि किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया।'' गौतम बुद्ध नगर का कबाड़ माफिया एवं गैंगस्कर रवि काना का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ दर्ज कई गंभीर मामलों के सिलसिले में वह बांदा जेल में बंद

था। नोएडा पुलिस के अनुसार, रवि काना गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में डी-190 के रूप में पंजीकृत एक संगठित आपराधिक गिरोह का सरगना है, जिसमें 18 सदस्य हैं। उसके खिलाफ कुल 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि उसके गिरोह के खिलाफ 131 मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने बताया कि गिरोह स्क्रैप व स्टील की चोरी व लूट, जबरन वसूली, व्यापारियों व बिल्डरों को धमकी देने सहित संगठित अपराधों तथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर व दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अपराध की आय से बेनामी संपत्तियां अर्जित करने में शामिल है। पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत फरवरी से नवंबर 2024 के बीच जारी अदालती आदेशों के आधार पर रवि काना, उसके परिजनों और संबंधित कंपनी की 92.65 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्तियां जब्त की गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि जब्त संपत्तियों में ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक भूखंड, बुलंदशहर की जमीन, कई व्यावसायिक वाहन, बैंक खाते और कई कंपनियां शामिल हैं, जिनका कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन को वैध में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

नोएडा पुलिस ने बताया कि 2023 में इकोटेक-3 थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में रवि काना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसकी शर्तों में पासपोर्ट जमा करना और जांच में सहयोग करना शामिल था। हालांकि, उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और कथित तौर पर एक जनवरी 2024 को बिना पासपोर्ट जमा किए विदेश चला गया। पुलिस के अनुसार, इसके बाद चार जनवरी 2024 को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और 24 अप्रैल 2024 को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

कार के नहर में गिरने से दो की मौत

जालौन। जिले में कोट्रा-ऐट मार्ग पर बुधवार को एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश में कार नहर में गिर गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। कोटरा थाने के प्रभारी विमलेश कुमार ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 11:30 बजे करथारा मोड़ के पास हुई।

उन्होंने बताया कि पच्छीपुरा गांव के रहने वाले जितेंद्र (50) और इंद्रपाल (55) किसी काम से कोटरा आए थे और वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। अधिकारी ने बताया कि टक्कर में मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया, जबकि कार में सवार लोगों ने कथित तौर पर तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की, जिससे चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और कार एक गहरी नहर में गिर गई। उन्होंने बताया कि आस-पास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को नहर से बाहर निकाला। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बस पटलने से तीन साल के बच्चे की मौत, एक दर्जन यात्री घायल

फिरोजाबाद। जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के दिल्ली से गोरखपुर जा रही एक डबल डेकर बस के अनियंत्रित होकर पलटने से तीन साल के बच्चे की मौत हो गयी, जबकि 12 यात्री घायल हो गए।

पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक को नींद आना बताया जा रहा है। बस में लगभग 45 यात्री सवार थे। नसीरपुर थाने के प्रभारी ज्ञानेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि दुर्घटना में लगभग 10-12 यात्रियों को मामूली चोटें आईं और सभी घायलों को सीएचसी शिकोहाबाद भेजा गया, जहां उनका उपचार किया गया ।

सोलंकी ने बताया कि इस दर्घटना में बस सवार यात्री कृष्ण यादव के तीन साल के बटे शुभ की मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को अपने साथ ले गए।

टीबी मरीज ने की अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या

शाहजहांपुर। जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज में टीबी का इलाज करा रहे 25 साल के एक युवक ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली। यह जानकारी पुलिस ने दी।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) पंकज पंत ने बताया कि सीतापुर जिले के महोली का रहने वाला अनुज कोतवाली पुलिस थानाक्षेत्र के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था और पिछले 11 दिनों से टीबी वार्ड में उसका उपचार किया जा रहा था। पंत के मुताबिक, मरीज की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसके परिवार वाले उसे इलाज के लिए शाहजहांपुर लाए

थे। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि मंगलवार आधी रात के आसपास, अनुज चुपके से वार्ड से बाहर निकल गया और अस्पताल की इमारत की दूसरी मंजिल से कूद गया।

अधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।

अतिक्रमण हटाने गई पुलिस, राजस्व कर्मियों पर पथराव, आठ लोग घायल

बलिया। जिले में अतिक्रमण रोधी अभियान के लिए पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया। इस घटना में पांच पुलिस कर्मियों और तीन राजस्व अधिकारियों सहित आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। घटना मंगलवार को उस समय हुई जब पुलिस और राजस्व विभाग की टीम खेजुरी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हथौज गांव में एक तालाब के किनारे अवैध अतिक्रमणों को हटाने गई थी।

अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई थी। उन्होंने बताया कि सिकंदरपुर के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के नेतृत्व में तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम तालाब के किनारे अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए गांव पहुंची तभी कुछ स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर दूसरों के बहकावे में आकर अचानक टीम पर पत्थर फेंके और बलवा किया।

थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि इस घटना में पांच पुलिस कर्मी और तीन राजस्व कर्मी सहित आठ लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दो नामजद व्यक्तियों और लगभग 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ खेजुरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में मनाया गया 40वां स्थापना दिवस

कक्षा आठ के विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ दी विदाई

गाजियाबाद। सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में 40वां स्थापना दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक हवन कर संपन्न हुआ। जिसमें फाउंडर व डायरेक्टर डॉ. माला कपूर, मुख्य अतिथि डॉ. मंगला वैद, प्रधानाध्यापिका सोनिया सेहरा एवं एकता कोहली, पूर्व प्रधानाध्यापिका रेनु चोपड़ा के अलावा अध्यापिका रोजी नागपाल व शीतल मित्तल सहित पूरे स्टाफ ने आहुति देते हुए छात्रों की उन्नति व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

डॉ. माला कपूर ने कहा कि चार दशक की शैक्षिक यात्रा में स्कूल ने अभिभावकों का विश्वास अर्जित किया और आज अधिकांश विद्यार्थी स्कूल के पूर्व छात्रों की दूसरी पीढ़ी के तौर पर इसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो पूरे स्टाफ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि स्कूल की स्थापना क्लीन गाजियाबाद, ग्रीन गाजियाबाद के तहत वृक्षारोपण की मुहिम से हुई थी। बीते चार दशकों में पर्यावरण को संरक्षित करने में मिले अभिभावकों व छात्रों के योगदान की भी उन्होंने सराहना की। नेहरू नगर स्थित सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में आयोजित भव्य समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन और विशिष्ट गुणों के लिए तीन विद्यार्थियों नमन, मान्या बजाज व माही बंसल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रमों में भारतीय संस्कृति का सुंदर समन्वय देखने को मिला। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने सभी अध्यापिकाओं को विशेष रूप से बनाए क्राउन (मुकुट) पहनाकर उनके प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान भाव प्रकट किया। कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 8 के विद्यार्थियों के सम्मान में भावनात्मक विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। जिसमें विदा होने वाले विद्यार्थियों को उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर आकर्षक टाइटिल प्रदान किए गए। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब भावनात्मक संगीत के साथ विद्यार्थियों ने अपनी प्रिय अध्यापिकाओं से विदा ली। बच्चों की भावनाओं ने शिक्षिकाओं को भावविभोर कर दिया। संपूर्ण आयोजन विद्यालय की संस्कार युक्त शिक्षा परंपरा और शिक्षक-विद्यार्थी के आत्मीय संबंधों का सुंदर उदाहरण रहा।

स्थापना दिवस व विदाई समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. माला कपूर ने कहा कि विद्यालय के चालीस वर्षों का यह सफर समर्पण, अनुशासन और निरंतर उन्नति की मिसाल रहा है। इन वर्षों में विद्यालय ने न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, संस्कार और मूल्यों को भी अपनी शिक्षा का आधार बनाया।विद्यालय के गत 39 वर्षों का यह सफर निरंतर उन्नति तथा उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा जो निश्चय ही प्रशंसा के योग्य है।

RCB की निगाह दूसरे खिताब पर, मिथक तोड़ने की कोशिश करेगा दिल्ली कैपिटल्स

वडोदरा। लीग चरण में खेल के प्रत्येक विभाग में अच्छा प्रदर्शन करके उत्साह से लबरेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम गुरुवार को यहां होने वाले महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के फाइनल में दूसरा खिताब जीतने की कोशिश करेगी जबकि पिछले तीन बार की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स की टीम खिताबी मुकाबले में हार के मिथक को तोड़ने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन दोनों टीम के हाल के प्रदर्शन को देखते हुए यह निश्चित है कि फाइनल में रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।

पूर्व चैंपियन आरसीबी ने इस सत्र में शानदार प्रदर्शन किया है और मुश्किल परिस्थितियों में वापसी करने की अपनी क्षमता भी साबित की है। इसी जुझारूपन की बदौलत उसने लगातार पांच जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करते हुए इतिहास रचा। वह डब्ल्यूपीएल में ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई। इस सत्र में आरसीबी की किसी न किसी खिलाड़ी ने जरूरत के समय अच्छा प्रदर्शन किया है जिससे उसे हराना किसी भी टीम के लिए चुनौती बन गई है। स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली आरसीबी दूसरा खिताब जीतकर मुंबई इंडियंस की बराबरी करना चाहेगी। पिछले दो मैच में उसने शानदार प्रदर्शन करके अच्छी लय के साथ फाइनल में प्रवेश किया है। उसने यूपी वॉरियर्स को पिछले

मैच में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ग्रेस हैरिस की 75 रन की तूफानी पारी से आठ विकेट से हराया जबकि गुजरात जायंट्स के खिलाफ गौतमी नाइक की 73 रन की पारी की मदद से 2024 की चैंपियन टीम ने 61 रन से जीत दर्ज की थी। आरसीबी की चिंता इस सत्र में उसके कुछ बल्लेबाजों के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा है। इनमें मंधाना, हैरिस, जॉर्जिया वोल और ऋचा घोष भी शामिल हैं लेकिन कुछ अवसरों पर उनका योगदान निर्णायक साबित हुआ है। वहीं तेज गेंदबाज नादिन डी क्लर्क और सायली सतघरे ने अहम मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका की नादिन डी क्लर्क ने इस सत्र में आठ मैचों में 15 विकेट लिए हैं जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर चार विकेट है।

फाइनल में उनकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती हैं। श्रेयांका पाटिल टीम को स्पिन विभाग में मजबूती प्रदान करती हैं, जिसका प्रमाण गुजरात जायंट्स के खिलाफ मिली जीत में देखने को मिला, जिसमें उन्होंने पांच विकेट लिए थे। मंधाना की टीम की खासियत एक संतुलित और महत्वपूर्ण क्षणों में शानदार प्रदर्शन करना है। वह उम्मीद कर रही होंगी कि कुछ और खिलाड़ी इस खिताबी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करके दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती को ध्वस्त करने में योगदान देंगे। दिल्ली कैपिटल्स इस बार नई कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वह फाइनल में पिछले तीन टूर्नामेंट में उपविजेता रहने के बाद पहली जीत के लिए बेताब हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी गेंदबाजी लाइनअप पर पूरा भरोसा जताया है, जिसमें तेज गेंदबाज चिनले हेनरी और नंदनी शर्मा ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है। नंदनी ने इस सत्र में अभी तक 16 विकेट लेकर भारतीय टीम में जगह बनाने का दावा पेश किया है। वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बल्लेबाजी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी लाइनअप भी लय में आने लगी है। गुजरात जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में लिजेल ली ने उपयोगी योगदान दिया, वहीं शेफाली वर्मा ने अपनी खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। शीर्ष क्रम की भरोसेमंद बल्लेबाज लौरा वोलवार्ट ने पूरे सत्र में टीम को वह स्थिरता प्रदान की है। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों से प्रभावित होकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही कैपिटल्स को काफी फायदा हुआ है। उसका प्रत्येक खिलाड़ी फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बेताब होगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को अगर मिथक तोड़ना है तो उसे खेल के महत्वपूर्ण अवसरों पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

टीम इस प्रकार हैं

- **दिल्ली कैपिटल्सः** जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), तानिया भाटिया, (विकेटकीपर), लुसी हैमिल्टन, चिनेले हेनरी, मारिजान काप, अलाना किंग, लिजेल ली, मिन्नू मणि, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, शैफाली वर्मा, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, प्रगति सिंह, एडडला स्रुजाना, लौरा वोलवार्ट।
- **रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः** स्मृति मंधाना (कप्तान), लॉरेन बेल, नादिन डी क्लर्क, ऋचा घोष (विकेटकीपर), ग्रेस हैरिस, दयालन हेमलता, गौतमी नाइक, श्रेयांका पाटिल, कुमार प्रथ्योशा, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, लिन्से स्मिथ, पूजा वस्त्राकर, जॉर्जिया वोल, राधा यादव।

मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा

एशियाई चैंपियनशिप: पिस्टल शूटर ईशा सिंह ने भारत को दिलाए दो स्वर्ण पदक

नई दिल्ली। ओलंपियन ईशा सिंह ने पिछले साल के अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए बुधवार को यहां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप (पिस्टल/राइफल) के पहले दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारत को टीम वर्ग में भी पीला तमगा दिलाने में मदद की, लेकिन विश्व चैंपियन सम्राट राणा को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इक्कीस वर्षीय ईशा ने फाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 239.8 अंक हासिल किए। उन्होंने चीनी ताइपे की दो निशानेबाजों चेंग येन चिंग (235.4, रजत) और यू ऐ वेन (217.7, कांस्य) के अलावा हमवतन सुरुचि सिंह की कड़ी चुनौती से पार पाकर सीनियर एशियाई चैम्पियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इस निशानेबाज ने पिछले साल चीन के निंगबो में आईएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2024 में 19 वर्ष की आयु में जकार्ता में अपना पहला महाद्वीपीय खिताब जीता था। पहले 10 शॉट के चरण के बाद फाइनल में बढ़त बनाने वाली 19 वर्षीय सुरुचि एलिमिनेशन राउंड में पिछड़ गईं और चौथे स्थान पर रहीं, जबकि पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने और आठ निशानेबाजों के फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय मनु भाकर सातवें स्थान पर रहीं।

ईशा ने संयम बनाए रखते हुए 10.4 और उससे अधिक के तीन स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक के लिए अपना दावा मजबूत किया जबकि इस बीच चीनी ताइपे की दोनों निशानेबाज पिछड़ गई। क्वालीफाइंग राउंड में सुरुचि 576 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि मनु और ईशा दोनों का स्कोर 575 रहा। इन तीनों ने फाइनल में जगह बनाई। सुरुचि (576), मनु (575) और ईशा (575) की तिकड़ी ने कुल 1726 अंकों के साथ टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता, जो क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीतने वाले वियतनाम (1713) और चीनी ताइपे (1711) से काफी अधिक था। इससे पहले विश्व चैंपियन सम्राट पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

पिछले साल काहिरा में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले सम्राट ने क्वालीफाइंग राउंड में 581 का स्कोर बनाकर दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई और लग रहा था कि वह अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने में सफल रहेंगे। लेकिन फाइनल में यह 21 वर्षीय खिलाड़ी 220.3 का स्कोर बनाकर उज्बेकिस्तान के व्लादिमीर स्वेचनिकोव (242.0) और कजाकिस्तान के वैलेरी रखिमजान (241.0) से पीछे तीसरे स्थान पर रहा। आठ निशानेबाजों के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी श्रवण कुमार चौथे स्थान पर रहे। भारत ने इस स्पर्धा में टीम रजत पदक जीता।

भारत की तरफ से सम्राट (581), श्रवण (578) और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता वरुण तोमर (573) ने कुल 1732 अंक बनाए। उज्बेकिस्तान के भी 1732 अंक थे लेकिन उसने मेजबान भारत के 52 के मुकाबले 58 'इनर 10' का स्कोर बनाया था और इसलिए उसे स्वर्ण पदक मिला। कजाकिस्तान 1731 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 118 निशानेबाजों का सबसे बड़ा दल उतारा है। कजाकिस्तान के 35 निशानेबाज इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं।

बार्सिलोना ने अल्बासेटे को 2-1 से हराकर कोपा सेमीफाइनल में

मैड्रिड। लामिन यामल और रोनाल्ड अरौजो ने प्रत्येक हाफ में एक-एक गोल किया, जिससे बार्सिलोना ने दूसरी श्रेणी की टीम अल्बासेटे को 2-1 से हराकर कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अल्बासेटे ने राउंड ऑफ 16 में रियाल मैड्रिड को हराकर सबको चौंका दिया था। बार्सिलोना की सभी टूर्नामेंटों में खेले गए पिछले 17 मैचों में यह 16वीं जीत है। वह लगातार चौथी बार कोपा सेमीफाइनल में पहुंचा है। उसने पिछले सत्र में रियाल मैड्रिड को हराकर खिताब जीता था। बार्सिलोना स्पेनिश लीग में शीर्ष पर है और रियाल मैड्रिड से एक अंक आगे है। कोपा का सेमीफाइनल दो चरणों में खेला जाएगा। फाइनल अप्रैल में सेविला में होगा।

चेल्सी को हराकर आर्सेनल इंग्लिश लीग कप के फाइनल में

लंदन। आर्सेनल ने इस सत्र में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चेल्सी को हराकर इंग्लिश लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। काई हावर्ट्ज ने सेमीफाइनल के दूसरे चरण में अपने पूर्व क्लब के खिलाफ स्टॉपेज टाइम में गोल किया जिससे आर्सेनल ने चेल्सी को 1-0 से हराया। इस तरह से उसने कुल मिलाकर 4-2 के अंतर से जीत हासिल की। आर्सेनल की टीम ने 2020 से कोई ट्रॉफी नहीं जीती है लेकिन इस सत्र में उसने अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसकी टीम प्रीमियर लीग में छह अंकों की बढ़त के साथ 2004 के बाद पहली बार इंग्लिश चैंपियन बनने की दौड़ में है और लगातार आठ जीत के बाद चैंपियंस लीग तालिका में भी शीर्ष पर है। इसके अलावा आर्सेनल एफए कप के चौथे दौर में भी पहुंच गया है।

हितेश और प्रीति की अगुवाई में भारतीय मुक्केबाजों की शानदार शुरुआत

लानुसिया (स्पेन)। हितेश गुलिया (70 किग्रा) और प्रीति (54 किग्रा) की शानदार जीत की बदौलत भारत ने बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। इस टूर्नामेंट में 21 देशों के 214 मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। हितेश ने 70 किग्रा भार वर्ग के एलीट पुरुष वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए नीदरलैंड के फिन बोस को 5-0 के अंतर से हराया। इससे पहले प्रीति ने महिलाओं के एलीट 54 किग्रा में कजाकिस्तान की अलियास्कर सिम्बैट पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की थी।

भारत की अन्य महिला खिलाड़ियों में प्राची (57 किग्रा), प्रिया (60 किग्रा) और काजल (65 किग्रा) ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। प्राची और प्रिया ने

क्रमशः स्पेन की वनेसा मोरेल रामिरेज और कनाडा की एलेशिया मानसुएटो पर 5-0 की एक समान जीत दर्ज की, जबकि काजल ने कजाकिस्तान के असीम तनातार को 4-1 से हराया।

पुरुषों के वर्ग में भारत के सचिन (60 किग्रा) ने स्पेन के ब्रैंडन एलेजांद्रो को 5-0 से जबकि मोहम्मद हुसामुद्दीन (60 किग्रा) ने डेनमार्क के मटियास मेहमत बुयुक्देमिर को 4-1 से हराया। अभिनाश जमवाल (65 किग्रा) ने डेनमार्क के क़ालिद उस्मान पर 5-0 की शानदार जीत के साथ प्रभावित किया।

दीपक (70 किग्रा) ने बेल्जियम के हॉर्नेल आयतेवी को 4-1 से हराया। आकाश (75 किग्रा) और अंकुश (80 किग्रा) ने भी 4-1 से जीत हासिल करके अगले दौर में प्रवेश किया, लेकिन आदित्य प्रताप यादव (65 किग्रा) इंग्लैंड के जो टर्नर से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

PSL में खेलेंगे विश्व कप की टीम से बाहर किए गए स्टीव स्मिथ

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए गए अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेलने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने नई फ्रेंचाइजी सियालकोट स्टैलियन्ज के साथ करार किया है। एशेज में शानदार प्रदर्शन करने और सिडनी सिक्सर्स के साथ बिग बैश लीग में बेहतरीन सत्र के बावजूद स्मिथ को टी20 विश्व कप के लिए नजरअंदाज कर दिया गया, जो सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। स्मिथ 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेना चाहते हैं जहां क्रिकेट की टी20 प्रारूप में वापसी होगी। इसलिए यह 36 वर्षीय खिलाड़ी टी20 प्रारूप की राष्ट्रीय टीम में वापसी करने के लिए बेताब है।

बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने म्यांमार को 5-0 से हराया

किंगदाओ (चीन)। मौजूदा चैंपियन भारतीय महिला टीम ने बुधवार को यहां ग्रुप वाई के अपने पहले मुकाबले में म्यांमार को 5-0 से हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। तन्वी शर्मा ने सबसे पहले कोर्ट में उतरकर थेट हटर थुजार को केवल 32 मिनट में 21-13 21-16 से हराया। इसके बाद रक्षिता श्री संतोष रामराज ने दूसरे एकल में ऐंट चिट फू को 21-12 21-6 से हराकर भारत को 2-0 से बढ़त दिला दी। मालविका बंसोड ने तीसरे एकल मुकाबले में लिन लिन हेट को 21-19 21-12 से हराकर भारत की जीत सुनिश्चित की। भारत ने इसके बाद युगल मुकाबलों में भी दबदबा बरकरार रखा और दोनों मैच सीधे गेम में जीते। प्रिया कोंजेंगबम और श्रुति मिश्रा की जोड़ी ने सु लैट और थेट हटर थुजार को 21-15 21-16 से हराया। इसके बाद त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को हेट और फू की जोड़ी को 21-8 21-6 से हराने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। भारत गुरुवार को अपने दूसरे ग्रुप मैच में पिछली बार के उपविजेता थाईलैंड से भिड़ेगा।

व्यापार समझौते अनिश्चितताओं को खत्म करते हैं, पूंजी सृजन में आती है तेजी: सेबी प्रमुख पांडेय

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को कहा कि अमेरिका जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों के जरिये व्यापारिक तनाव खत्म होने से अनिश्चितताएं दूर होती हैं जिससे पूंजी सृजन में तेजी आने में मदद मिलती है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के विदेशी निवेशकों को देश में अधिक धन लगाने के लिए प्रेरित करने के सवाल पर पांडेय ने कहा कि ऐसे कदम निवेश संबंधी फैसलों को ''प्रोत्साहित'' कर सकते हैं।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि मूल रूप से जब किसी नियामकीय कार्रवाई का बोझ हटता है और व्यापारिक तनाव खत्म होते हैं, तो पूंजी सृजन की प्रक्रिया हमेशा तेज होती है। सेबी प्रमुख ने कहा कि अनिश्चितताओं के दूर होने से निवेश निर्णयों को बल मिलता है और पूंजी को लेकर अधिक समझ आती है। उन्होंने कहा

कि कुल मिलाकर मौजूदा हालात में कहा जा सकता है कि व्यापार से जुड़े जो समझौते हुए हैं, उनसे काफी हद तक अनिश्चितताएं दूर हुई हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूती देने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के इतर बातचीत करते हुए पांडेय ने वायदा-विकल्प सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव पर टिप्पणी करने से हालांकि इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय हम किसी भी नए कदम पर विचार नहीं कर रहे हैं और जो ढांचा हमने लागू किया है, वही जारी रहेगा।'' साप्ताहिक 'एक्सपायरी' पर एक सवाल और सेबी के इन्हें प्रतिबंधित करने पर विचार करने के सवाल पर उन्होंने दोहराया कि नियामक इस मामले में यथास्थिति बनाए रखेगा। इस बीच, बॉन्ड बाजार को मजबूत करने की जरूरत पर पांडेय ने कहा कि सेबी के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अधिक निवेशक बॉन्ड बाजार की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में बॉन्ड बाजार में स्वागतयोग्य वृद्धि हुई है, लेकिन बाजार को और मजबूत करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

इसमें शीर्ष रेटिंग वाली कंपनियों के अलावा अन्य जारीकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाना, अधिक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम सुनिश्चित करना और वित्तीय सेवा क्षेत्र से बाहर की कंपनियों को भी इस मार्ग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। पांडेय ने कहा कि पूंजी बाजार नियामक ने बॉन्ड बाजार के लिए ''उचित विनियमन'' का दृष्टिकोण अपनाया है। हालांकि, उन्होंने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों से साथ आने का आग्रह किया।

बीएसई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदररमन राममूर्ति ने एक निश्चित सीमा से अधिक वित्त जुटाने के लिए सार्वजनिक निर्गम के जरिये कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार तक पहुंच को अनिवार्य करने और जारीकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट देने का सुझाव दिया। बीएसई और एनएसई के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में हितधारकों ने अपनी मंशा को बेहतर तरीके से व्यक्त करने के लिए '' बॉन्ड्स – एक सशक्त बंधन'' टैगलाइन भी पेश की।

आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट से बाजार की बढ़त सीमित, सेंसेक्स 79 अंक चढ़ा

मुंबई। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में तेज गिरावट आने से घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 79 अंक की बढ़त पर रहा जबकि निफ्टी 48 अंक चढ़कर बंद हुआ। कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी और कच्चे तेल के दाम में तेजी से भी निवेशक धारणा प्रभावित हुई। हालांकि, चुनिंदा शेयरों में तेजी से सूचकांक हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। पिछले कारोबारी सत्र में जोरदार उछाल के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 78.56 अंक यानी 0.09 प्रतिशत बढ़कर 83,817.69 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान यह 83,947.53 अंक के उच्चस्तर तक गया और 83,119.95 अंक के निचले स्तर तक आया। इस तरह इसमें 827.58 अंक का उतार-चढ़ाव देखा गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 48.45 अंक यानी 0.19 प्रतिशत चढ़कर 25,776 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में इटर्नल, ट्रेंट, एनटीपीसी, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और मारुति सुजुकी प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए। इन शेयरों में सात प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख आईटी कंपनियों में तेज गिरावट की वजह से बीएसई आईटी सूचकांक 5.49 प्रतिशत लुढ़ककर 35,109.51 पर बंद हुआ।

ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पोनमुडी आर. ने कहा, ''तेल एवं गैस, टिकाऊ उपभोक्ता सामान, धातु और वाहन शेयरों में मजबूत बढ़त देखी गई, जबकि वैश्विक प्रौद्योगिकी शेयरों में कमजोरी के चलते आईटी शेयरों पर बिकवाली का दबाव रहा।'' उन्होंने कहा कि एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक की तरफ से समूची कार्यप्रणाली को स्वचालित करने वाला टूल पेश किए जाने से यह चिंता बढ़ी कि एआई में तीव्र प्रगति पारंपरिक सॉफ्टवेयर कारोबारी मॉडल को प्रभावित कर सकती है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 5,236.28 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,014.24 करोड़ रुपये का निवेश किया।

इंडिगो ने लंबी दूरी के उड़ान में किया बदलाव 17 फरवरी से कोपनहेगन के लिए सेवा स्थगित

नई दिल्ली। इंडिगो ने बुधवार को विदेशी परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण अपने लंबी दूरी के उड़ान कार्यक्रम में बदलाव करने की घोषणा की। इसके तहत 17 फरवरी से कोपनहेगन (डेनमार्क) के लिए उड़ानों का संचालन स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एयरलाइन दिल्ली-लंदन हीथ्रो और दिल्ली-मैनचेस्टर मार्गों पर भी उड़ानों की संख्या में कटौती करेगी।

कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि उसके बड़े आकार के विमानों को परिचालन से संबंधित बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हवाई क्षेत्र की लगातार बदलती परिस्थितियां और भारत के साथ-साथ विदेशों में भी हवाई अड्डों पर अत्यधिक भीड़ जैसे कारण

शामिल हैं। बयान के अनुसार, इन कारकों के कारण उड़ानों के समय में काफी वृद्धि हुई है, जिससे लंबी दूरी के मार्गों पर संचालित होने वाले छह 787-9 विमानों का परिचालन कार्यक्रम प्रभावित हुआ है।

नेटवर्क समायोजन के हिस्से के रूप में, एयरलाइन 17 फरवरी से अगले आदेश तक कोपनहेगन के लिए उड़ानों को निलंबित रखेगी। दिल्ली-मैनचेस्टर मार्ग पर सात फरवरी से उड़ानों की संख्या साप्ताहिक पांच से घटाकर चार कर दी जाएगी। 19 फरवरी से इस मार्ग पर उड़ानों की संख्या और कम कर साप्ताहिक तीन कर दी जाएगी। इसके अलावा, दिल्ली-लंदन हीथ्रो मार्ग पर भी उड़ानों की संख्या कम की जाएगी। वर्तमान शीतकालीन समय-सारणी के तहत नौ फरवरी से इस मार्ग पर उड़ानों की संख्या पांच से घटाकर चार प्रति सप्ताह कर दी जाएगी। इंडिगो ने कहा कि यह कदम 'कनेक्टिंग फ्लाइट' छूटने और उड़ानों में होने वाली देरी से यात्रियों को बचाने के लिए उठाया गया है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

रुपया 11 पैसे टूटकर 90.43 प्रति डॉलर पर

मुंबई। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति की घोषणा के बाद पिछले कारोबारी सत्र में आई तेजी के बाद बुधवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 90.43 (अस्थायी) पर आ गया। यह गिरावट कॉरपोरेट और आयातकों द्वारा डॉलर की संभावित खरीदारी के कारण हुई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति के बाद सकारात्मक माहौल के बावजूद अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि अभी तक कोई हस्ताक्षरित या आधिकारिक रूप से जारी व्यापार समझौता नहीं हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.35 पर खुला और कारोबार के दौरान 90.26 के उच्चस्तर तथा 90.54 के निचले स्तर घूमता रहा। अंत में घरेलू मुद्रा 90.43 (अस्थायी) पर बंद हुई, जो पिछले बंद स्तर से 11 पैसे कम है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मंगलवार को सहमति होने के बाद भारतीय रुपया एशिया की सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरा था। उस दिन रुपये ने एक ही कारोबारी सत्र में 117 पैसे या 1.28 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की थी और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 90.32 पर बंद हुआ था।

दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में सुधार से 2026-27 में ईवी दोपहिया वाहनों की बिक्री 16-18 प्रतिशत बढ़ने के आसार

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मात्रा वृद्धि अगले वित्त वर्ष में दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति में सुधार से 16-18 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं के कारण इसके 12-13 प्रतिशत तक सीमित रहने का अनुमान है। क्रिसिल रेटिंग्स ने यह जानकारी दी।

रेटिंग एजेंसी ने बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की वृद्धि अस्थायी रूप से दुर्लभ खनिजों (रेयर-अर्थ मैग्नेट) की आपूर्ति में व्यवधान और आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) मॉडलों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के युक्तिकरण के कारण धीमी रहने के आसार है। गत वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया की मात्रा वृद्धि 22 प्रतिशत रही थी।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, '' दुर्लभ खनिजों की कमी से उत्पन्न आपूर्ति व्यवधान ने साल के मध्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों मात्रा को प्रभावित

किया। जैसे-जैसे उपलब्धता में सुधार हुआ और आईसीई मॉडल में जीएसटी आधारित मूल्य संशोधन हुआ, मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) ने छूट दी और कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक मॉडल पेश किए ताकि आईसीई-ईवी मूल्य अंतर को कम किया जा सके।''

उन्होंने कहा कि इससे हाल के महीनों में बिक्री में सुधार हुआ है लेकिन पहले के आपूर्ति व्यवधान का असर पूरे साल की वृद्धि को 12-13 प्रतिशत तक सीमित रख सकता है। सेठी ने कहा, '' आपूर्ति स्थितियों में सुधार के साथ (जिसमें चीन से मैग्नेट की आपूर्ति धीरे-धीरे फिर शुरू होना और ओईएम द्वारा सोर्सिंग में विविधता लाने के शुरुआती कदम शामिल हैं) अगले वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि 16-18 प्रतिशत तक दोबारा तेज होने की उम्मीद है। बशर्ते दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता स्थिर बनी रहे।''

'मां बहन' में कॉमिक अंदाज में नजर आयेंगी

तृप्ति डिमरी

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी अपनी आने वाली फिल्म 'मां बहन' में कॉमिक अंदाज में नजर आयेंगी। 'बुलबुल' और 'क़ाला' के बाद, तृप्ति डिमरी अपनी अगली नेटफ्लिक्स फिल्म 'मां बहन' के साथ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। यह एक डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसे सुरेश त्रिवेणी ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, रवि किशन और धारणा दुर्गा की भी अहम भूमिका है। इस फिल्म की कहानी रेखा और उसकी दो बेटियों, जया और सुषमा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें उनके मोहल्ले में पहले से ही शक की नजर से देखा जाता है। कहानी तब मजेदार मोड़ लेती है, जब उनकी रसोई में एक लाश मिलती है और उसे छुपाने के लिए तीनों को मजबूरी में साथ आना पड़ता है। फिल्म मां बहन का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है। तृप्ति डिमरी का डार्क कॉमेडी की ओर रुख करना दर्शकों को खासा पसंद आ रहा है। उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग, 'बड़ी बहन' के किरदार में जिम्मेदारी और हल्की-फुल्की शरारत, साथ ही उनकी सहज घरेलू बोली उनके किरदार को बेहद असली बनाती है। यही वजह है कि दर्शक उनके इस नए अंदाज़ को खूब सराह रहे हैं। 'ओ' रोमियो' में गंभीर और सधी हुई अदाकारी दिखाने के बाद, 'मां बहन' में तृप्ति डिमरी का यह चुलबुला और अनदेखा रूप सामने आ रहा है। यह साफ दिखाता है कि तृप्ति डिमरी आज की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो हर किरदार में आसानी से ढल जाती हैं।

रणदीप हुड्डा ने फिल्म 'ईथा' के लिए बढ़ाया वज़न और बनाई दमदार बॉडी

मुंबई। बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा नेअपनी आने वाली फिल्म 'ईथा' के लिए वज़न बढ़ाया है और दमदार बॉडी बनाई है। रणदीप हुड्डा ने एक बार फिर अपनी फिटनेस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस बार उन्होंने जिम से एक मिरर सेल्फी शेयर की है, जिसमें उनका बढ़ा हुआ और दमदार शरीर साफ नज़र आ रहा है। हाल ही में अपने नए मूंछों वाले लुक को लेकर चर्चा में रहे रणदीप अब इस नई शर्टलेस तस्वीर में अपनी जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते दिखे। यह लुक उनकी आने वाली फिल्म 'ईथा' के लिए है, जिसकी शूटिंग इस वक्त मुंबई में चल रही है। तस्वीर शेयर होते ही कमेंट सेक्शन में फैंस की भरमार हो गई। लोग आग और लाल दिल वाले इमोजी जमकर पोस्ट करने लगे। एक फैन ने लिखा कि भाई, वज़न बढ़ाना और घटाना कोई आपसे सीखे! वहीं किसी ने उन्हें सीधा 'हॉटेस्ट' कह दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर उत्साह इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि यह लुक फैंस के लिए पूरी तरह नया नहीं था। कुछ दिन पहले ही रणदीप को मुंबई में शूट के बाद देखा गया था, जहां उनकी घनी मूंछें और पहले से ज़्यादा भारी-भरकम बॉडी नज़र आई थी। उस वक्त का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और उनका नया लुक चर्चा का विषय बन गया था। रणदीप हुड्डा अपने किरदारों के लिए शरीर में बड़े बदलाव करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए फैंस को पूरा भरोसा है कि यह दमदार बॉडी उनकी अगली फिल्म 'ईथा' के लिए ही है। यह फिल्म मैडॉक फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है और इसका निर्देशन लक्ष्मीकांत उतेकर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "रणदीप अपने काम को लेकर हमेशा बेहद गंभीर रहते हैं। किसी किरदार के लिए अगर खास लुक या बॉडी की जरूरत होती है, तो वह पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। 'ईथा' के लिए भी वह अपनी ताकत बढ़ाने और बॉडी को और भारी बनाने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

अभिषेक पाठक की हाई-वोल्टेज ड्रामा फिल्म 'हाउसवाइफ' में दिखेंगी आलिया भट्ट

अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म 'एल्फा' को लेकर चर्चा में हैं, जो इसी साल रिलीज होने वाली है। इसी बीच खबर है कि उन्होंने एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी है। बताया जा रहा है कि आलिया निर्देशक अभिषेक पाठक के साथ हाई-वोल्टेज ड्रामा फिल्म 'हाउसवाइफ' में नजर आएंगी। अभिषेक पाठक इससे पहले अजय देवगन अभिनीत सुपरहिट फिल्म 'दृश्यम-2' का निर्देशन कर चुके हैं। इस नई फिल्म में आलिया एक विवाहित महिला की भूमिका निभाती दिखाई देंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की कहानी एक शादीशुदा जोड़े के इर्द-गिर्द घूमेगी और इसमें रिश्तों की जटिलताओं को भावनात्मक अंदाज में दिखाया जाएगा। मुख्य पुरुष किरदार के लिए अभिनेता राजकुमार राव से बातचीत जारी है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है, हालांकि अभी आधिकारिक अनुबंध नहीं हुआ है। अगर बात बनती है, तो यह पहली बार होगा जब आलिया भट्ट और राजकुमार राव बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि 'हाउसवाइफ' में आलिया केवल अभिनय ही नहीं करेंगी, बल्कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस के जरिए सह-निर्माता की भूमिका भी निभाएंगी। इस फिल्म का निर्माण पैनोरमा स्टूडियोज के साथ मिलकर किया जाएगा। शूटिंग 2026 के मध्य, यानी अगस्त या सितंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है। तब तक अभिषेक पाठक 'दृश्यम 3' की शूटिंग पूरी कर चुके होंगे। आलिया फिलहाल संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वार' में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ काम कर रही हैं।

फिल्म 'इक्का' का टीज़र रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेतासनी देओल और अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्म 'इक्का' का टीज़र रिलीज हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने फिल्म 'इक्का' का टीज़र सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि कानून या खून का रिश्ता, किसके हाथ में है इस खेल का इक्का? देखिए 'इक्का', जल्द आ रही है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। टीज़र में सनी देओल एक दमदार वकील के किरदार में नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अक्षय खन्ना इस फिल्म में नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं।सनी ने इस टीजर में सिर्फ एक डायलॉग 'शट अप' बोला है। टीजर में अक्षय खन्ना की झलक भी देखने को मिली है। उनका अंदाज़ भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। सनी देओल के साथ उनका तीखा आमना-सामना दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। अक्षय खन्ना का भी एक डायलॉग है। उन्होंने सिर्फ 'टिक टिक बूम' बोला है। फिल्म इक्का कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें कानून, रिश्ते और नैतिक दुविधाओं की टक्कर देखने को मिलेगी।

जयशंकर, रुबियो ने व्यापार समझौते का स्वागत किया

ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, प्रौद्योगिकी एवं महत्वपूर्ण खनिजों पर हुई चर्चा

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुए व्यापार समझौते का 'स्वागत' किया और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन पर द्विपक्षीय सहयोग को 'औपचारिक रूप देने' पर मंगलवार को चर्चा की।

बुधवार को अमेरिका द्वारा आयोजित होने वाली पहली महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले, रुबियो ने वाशिंगटन डीसी में मंगलवार को विदेश मंत्रालय में जयशंकर के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। बैठक के बाद जयशंकर ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि आज दोपहर अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से मिलकर बेहद प्रसन्नता हुई। द्विपक्षीय सहयोग के एजेंडे, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। उन्होंने लिखा कि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के जिन पहलुओं पर चर्चा हुई उनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी शामिल थे। हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्रों की बैठकें शीघ्र आयोजित करने पर सहमति बनी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट द्वारा जारी द्विपक्षीय बैठक के विवरण में कहा गया है कि रुबियो और जयशंकर ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की सहमति से हुए व्यापार समझौते का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने नए आर्थिक अवसरों को खोलने और साझा ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोकतंत्रों के एक साथ मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया। पिगॉट ने कहा कि रुबियो और जयशंकर ने 'महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को औपचारिक रूप देने' पर चर्चा की। बयान में कहा गया कि रुबियो और जयशंकर ने 'क्वाड के माध्यम से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया।

उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है।'

रुबियो ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने जयशंकर से मुलाकात कर 'महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर द्विपक्षीय सहयोग और दोनों देशों के बीच नए आर्थिक अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने पर चर्चा की। हमने अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापार समझौते की भी सराहना की।' जयशंकर दो से चार फरवरी तक अमेरिका की यात्रा पर हैं और बुधवार को विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ओर से बुलाई गई महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक में वह हिस्सा लेंगे। जयशंकर और रूबियो के बीच यह मुलाकात ट्रंप के 'ट्रुथ सोशल' पर यह घोषणा करने के एक दिन बाद हुई कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले जवाबी शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा।

ग्रीस में कोस्ट गार्ड के जहाज की प्रवासी नाव से टक्कर में 15 लोगों की मौत

एथेंस । ग्रीस और तुर्किये के मध्य स्थित एजियन सागर में चियोस द्वीप के तट पर ग्रीक कोस्ट गार्ड के एक गश्ती जहाज एवं प्रवासियों और शरणार्थियों को ले जा रही एक नाव के बीच टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 14 के शव समुद्र से बरामद किए गए।

ग्रीक नेशनल ब्रॉडकास्टर ईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार, बचाए गए 24 प्रवासियों में से एक की पास के अस्पताल में चोटों के कारण मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में 11 पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। यह दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार रात लगभग 9:00 बजे हुई। घायलों में कई बच्चे और दो गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। दोनों महिलाएं चोट सह नहीं पाईं और कथित तौर पर गर्भपात हो गया। नेशनल इमरजेंसी एड सेंटर के अनुसार, बचाए गए ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें आईं। कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। इस अभियान में चार कोस्ट गार्ड जहाज, स्वयंसेवी गोताखोरों को ले जा रही एक निजी नाव और एक हेलेनिक वायु सेना का हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

ग्रीक के सरकारी रेडियो ईपीटी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, घायलों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। रात लगभग 12 बजे घायलों में से एक महिला को चियोस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में दस बच्चे हैं। इसी बीच, दो कोस्ट गार्ड अधिकारी भी घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ओइनौसेस के मेयर जियोर्गोस डैनियल ने कहा कि गश्ती जहाज ओइनौसेस में था। उसी ने प्रवासी नाव को देखा। ग्रीक के समाचार आउटलेट प्रोटोथेमा की रिपोर्ट के अनुसार, चियोस का यह वाकया कोस्ट गार्ड और प्रवासी तस्करों के बीच हुई टक्कर का नतीजा है। कोस्ट गार्ड के गश्ती जहाज पर छोटी नाव पर सवार तस्करों ने ही पैंतरेबाजी करते हुए टक्कर मारी। इससे अफरातफरी मच गई। कोस्ट गार्ड की कार्रवाई में कई प्रवासी मारे गए। कई घायल हो गए। यह लोग मर्सिनिडी इलाके के बताए गए हैं। इस दौरान गोलीबारी की भी खबरें हैं। मगर इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि नाव में लगभग 35 लोग सवार थे।

गाजा में इजराइली हमले में 17 लोगों की मौत

दीर अल बलाह (गाजा पट्टी)। गाजा में इजराइली गोलीबारी में कम से कम 17 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

वहीं, इजराइल का कहना है कि आतंकियों की तरफ से की गई गोलीबारी में उसका एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई की। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि इजराइली गोलीबारी में सात महिलाओं और पांच बच्चों की मौत हो गई। दस अक्टूबर, 2025 को लागू हुए संघर्षविराम के बाद से फलस्तीनियों की मौत की ये ताजा घटना है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते के लागू होने के बाद से इजराइली गोलीबारी में 530 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। गाजा शहर के शिफा अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सेल्मिया ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि गाजा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ नरसंहार वाली जंग जारी है। संघर्षविराम कहां है? मध्यस्थ कहां हैं? अस्पताल ने बताया कि बुधवार सुबह इजराइली सैनिकों ने उत्तरी गाजा के तुफाह इलाके में एक इमारत पर गोलीबारी की। उसने बताया कि इस हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर एक ही परिवार के थे।

अमेरिका-ईरान के बीच ड्रोन हमले की घटना से वार्ता की संभावना धूमिल

काहिरा। ईरानी सशस्त्र बलों के एक ड्रोन ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में एक 'निरीक्षण मिशन' पूरा किया, जिसके ठीक बाद अमेरिकी सेना ने माना कि उसने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है जिसने एक विमान वाहक के करीब आक्रामक रूप से आने की कोशिश की थी।

ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि ईरान का अपने एक ड्रोन से संपर्क टूट गया है जिसके कारणों की जांच की रही है। फ़ार्स समाचार एजेंसी ने अज्ञात सूत्रों का हवाले से कहा कि ड्रोन ने ईरान से सटे क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों की सफलतापूर्वक निगरानी की और वास्तविक समय में जमीनी ठिकानों को डेटा भेजा। रिपोर्ट में ऐसे अभियानों को क्षेत्र की समग्र निगरानी के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इससे पहले कहा था कि अरब सागर में एक अमेरिकी एफ-35सी युद्धक विमान को ईरानी शाहेद-139 ड्रोन को मार गिराने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमान ने कहा कि ईरानी ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर 'अनावश्यक रूप से पैंतरेबाजी' की, जब विमानवाहक पोत ईरानी तट से लगभग 800 किलोमीटर दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से गुजर रहा था। अमेरिकी बयान के अनुसार, ड्रोन को आत्मरक्षा की कार्रवाई में मार गिराया गया। अमेरिकी सेना ने कहा कि इस मुठभेड़ में कोई भी अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ और न ही किसी उपकरण को नुकसान पहुंचा। यह मुठभेड़ आने वाले दिनों में अमेरिका-ईरान वार्ता की अस्थायी संभावनाओं के बीच हुई है। इससे पहले दिन में, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा था कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को अमेरिका के साथ निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बातचीत करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्री पेज़ेश्कियन ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय सरकारों द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वार्ता प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने के अनुरोध के बाद उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि कोई भी वार्ता 'गरिमा, विवेक एवं तत्परता' की सीमाओं में होनी चाहिए। तुर्की ने इस मामले में मध्यस्थता की पेशकश की है लेकिन ईरान बातचीत के दायरे को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी समाचार एजेंसी एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरान वार्ता स्थल के रूप में ओमान को प्राथमिकता देता है और अरब एवं मुस्लिम देशों को शामिल करने वाले व्यापक प्रारूप के बदले अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करना चाहता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बग़ाई ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाली वार्ताओं के लिए स्थान तय करने के लिए विचार-विमर्श जारी है। यह जानकारी आधिकारिक समाचार पत्र आईआरएनए ने दी।

श्री बग़ाई ने कहा कि तुर्की, ओमान और कई अन्य क्षेत्रीय देशों ने वार्ताओं की मेज़बानी करने के लिए तत्परता व्यक्त की है जिन्हें ईरान अत्यंत महत्व देता है। हालांकि इस राजनयिक प्रयास का इज़रायल ने विरोध किया है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मंगलवार को यरुशलम पहुंचे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ से बातचीत की।